MR. DEPUTY- SPEAKER : May I request the hon. Member, if she so desires, to continue her speech the next day? We have now to take up some other item of business.

DR. SUSHILA NAYAR : I will not be here tomorrow. So, unless you want me not to continue my speech, you may allow me to conclude it today.

MR. DEPUTY- SPEAKER: I am sorry, I cannot help it. We have to take up some other business now.

14·29 hrs.

MOTION AND STATUTORY RESOLUTION *Re* : PROCLAMATION IN RESPECT OF HARYANA

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "That this House regrets that the Government of India did not reject the report dated the 17th November, 1967 of the Governor of Haryana to the President recommending the issue of proclamation, laid on the Table of the House on the 21st November, 1967 inasmuch as the Government of Haryana enjoyed majority in the Legislature and functioned in accordance with the provisions of the Constitution."

आम चुनावों के बाद भारतीय लोकतंत्र की जो शक्ति प्रकट हुई थी आज उस पर आघात लगाया गया है । शान्तिपूर्ण तरीके से एक क्रान्ति करके जनता ने अपनी इच्छा से अपनी सरकार चुनने के जिस मताधिकार के महत्व का परिचय दिया था आज उस अधिकार पर चोट मारी गई है। आज राष्ट्रपति ने एक घोषणा करके हरियाणे की निर्वाचित विधान सभा को भंग कर दिया। यह कार्यवाही हरियाणे के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर की गई । यह रिपोर्ट भारत सरकार को 17 नवम्बर को भेजी गई । संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार है कि वह राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या किसी अन्य जरिये से सूचना मिलने पर, संतुष्ट हो कर इस बात का निर्णय करें कि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है । स्पष्ट है कि इस मामले में अन्य सूत्रों का उपयोग नहीं किया गया है । राष्ट्रपति का निर्णय राज्यपाल की रिपोर्ट पर आधारित है । राज्यपाल की रिपोर्ट हमारे सामने है । शायद सभी माननीय सदस्यों को उसका अध्ययन करने का मौका नहीं मिला होगा । मैं उस रिपोर्ट पर बाद में आऊंगा ।

किसी राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलता, केन्द्र सरकार इस बात के लिये बंधी हुई नहीं है कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करे । केन्द्र सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करना है, किन्तु वह राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकती है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अभी सम्बद्ध राज्य में संविधान को स्थगित करने का अवसर नहीं आया है । मेरी पहली शिकायत केन्द्र सरकार से है । क्या केन्द्र सरकार आंख मूंद कर राज्यपाल की रिपोर्ट को स्वीकार करेगी ? क्या केन्द्र सरकार ने स्वयं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार किया ? मैंने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें इस बात पर खेद प्रकट किया है कि केन्द्र सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत नहीं किया । मैं गृह मंत्री से जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया ।

ऐसे उदाहरण हो चुके हैं, जब राज्यपालों को उनकी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिये रिपोर्ट वापस कर दी गई । इस मामले में केन्द्र सरकार ने यह रुख क्यों नहीं

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अपनाया ? क्या इसका कारण यह था कि जो सरकार भंग होनी थी, वह एक ग़ैर-कांग्रेसी सरकार थी और केन्द्र में बैठी हुई कांग्रेस अब किसी भी ग़ैर-कांग्रेसी सरकार को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है ? राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि जिस दिन, अर्थात् 17 नवम्बर को, यह रिपोर्ट की गई, उस दिन भी राव वीरेन्द्रसिंह मंत्रिमंडल को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त था । राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा है कि मंत्रिमंडल विधान सभा का बहुमत खो बैठा है, अल्पमत में शासन चला रहा है । अल्पमत-शासन चलाने से संविधान के प्रावधानों पर आघात होने की बात समझ में आ सकती है, यद्यपि वह सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका निर्णय विधान सभा में होना चाहिये, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल यह नहीं कहते कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में हो गई है और बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ।

17 तारीख़ को चौधरी देवीलाल के गुट के सदस्यों द्वारा कांग्रेस में मिलने के बाद भी और अपनी मुख्य रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने के बाद भी राज्यपाल ने राष्ट्रपति जी को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 78 सदस्यों के सदन में राव मंत्रिमंडल को 40 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है । राव सरकार को इसलिए भंग नहीं किया जा रहा है कि वह बहुमत में नहीं रही, बल्कि राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध में बड़े विचित्र कारण दिये हैं ।

संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को अपने को संतुष्ट करना है कि सम्बद्ध प्रदेश की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है । मैं संविधान को उद्धृत करता हूं :

> "If the President on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution....."

मगर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में कहते हैं—मैं उसमें से उद्धृत कर रहा हूं :—

> "It is my considered opinion that a situation has arisen in Haryana in which a stable Government cannot be carried on....."

संविधान में "स्टेबल" शब्द नहीं है । कोई सरकार स्थायी है या अस्थायी है, टिकाऊ है या कल गिर जायेगी, यह प्रश्न अलग है । किसी राज्यपाल की दृष्टि में कोई सरकार टिकाऊ नहीं है, इसलिए वह राष्ट्रपति को यह सिफ़ारिश नहीं कर सकता कि उस राज्य की विधान सभा भंग कर दी जाय, मंत्रिमंडल समाप्त कर दिया जाये और जनता पर राष्ट्रपति-शासन लागू कर दिया जाये । राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में "स्टेबल" शब्द जोड़ दिया है, जिसे संविधान के निर्माताओं ने कहीं स्थान नहीं दिया । यह राज्यपाल की अनधिकार चेष्टा है, जिस पर इस सदन को गम्भीरता के साथ विचार करना होगा ।

राज्यपाल दूसरी बात यह कहते हैं :—

> "The Government has also sought to maintain itself precariously in power by creating too many Ministers which is an abuse of its constitutional powers".

संविधान में कहा गया कि अगर कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार न चले,—आदि । राज्यपाल महोदय इस बात के दो कारण देते हैं कि हरियाणा की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है । उन में से एक कारण यह है कि सरकार ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करके मंत्रियों की संख्या बढ़ा ली । क्या संविधान या संविधान

का कोई प्रावधान मंत्रियों की संख्या तय करता है ? क्या मंत्रियों की संख्या बढ़ाने मात्र से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है ? क्या केवल इस आधार पर किसी मंत्रि-मंडल को बर्खास्त करने का तानाशाही कदम उठाया जा सकता है ? यह सुझाव अलग है कि संविधान में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों की संख्या निश्चित होनी चाहिये । अगर इसके लिए कोई संशोधन आया, तो हम उस पर विचार करने के लिये स्वतंत्र होंगे । लेकिन जब तक संविधान मौन है, तब तक इस सवाल पर किसी सरकार को भंग नहीं किया जा सकता है । मंत्रियों की बरात किसी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं देती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह सिफ़ारिश करे कि अब संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल सकता है ।

अभी केन्द्र में मंत्री बढ़ाए गए हैं, उपमंत्रियों की संख्या में वृद्धि की गई है । जब यहां संख्या में वृद्धि की जाती है, तो यह तर्क दिया जाता है कि हम नये लोगों को प्रशिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई ग़ैर-कांग्रेसी सरकार मंत्री बढ़ाती है, तो संविधान ख़तरे में पड़ जाता है । उस दिन इस सदन में यह आरोप लगाया गया कि प्रधान मंत्री के केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जो सदस्य बढ़ाए हैं, वे इस लिए बढ़ाए हैं कि कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ कर जाना चाहते थे, वे न जायें ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : ग़लत है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो फिर हरियाणा में जो मंत्री बढ़ाए गये हैं, वे केवल उसी कारण को ध्यान में रख कर बढ़ाये गये हैं, जिसका उल्लेख राज्यपाल ने किया है, यह तर्क कैसे दिया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष जी, जब हरयाणा का राज्य बना उस समय क्या स्थिति थी ? मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । 1 नवम्बर, 1966 को हरयाणा का पृथक राज्य बना । सदन के कुल सदस्यों की संख्या 54 थी । उसमें 48 कांग्रेसी के थे, तीन जनसंघ के, दो निर्दलीय और एक संसोपा का सदस्य था । कांग्रेस के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष थे । शेष 46 सदस्यों में से हरयाणा की प्रथम कांग्रेसी सरकार में 22 मंत्री बनाए गए । उस समय मंत्रि-मंडल को कोई खतरा नहीं था । उस समय विरोधी दल किसी को अपने साथ मिला लेंगे इस बात की आशंका नहीं थी । सामान्य काल में जब हरयाणा के मंत्रिमंडल को पूर्ण समर्थन प्राप्त था तब 46 में से 22 मंत्री बनाये गये । उस समय गवर्नर ने मंत्रियों की संख्या बढ़ाने पर संविधान संकट में पड़ा है, इसकी अनुभूति नहीं की । उस समय उन्होंने मंत्रियों के बढ़ाने पर आपत्ति नहीं की । उस समय चुनाव निकट आ रहा था । राजनैतिक दृष्टिकोण सामने रख कर मंत्री बढ़ाए गए थे । लेकिन राज्यपाल टुकुर-टुकुर देखते रहे । संविधान की रक्षा का दायित्व उस समय उन्होंने नहीं निभाया । और आज जब ग़ैर-कांग्रेसी सरकार मंत्री बढ़ाती है तो फिर राज्यपाल उस मंत्रिमंडल को बरखास्त करने के लिये ऐसे हास्यास्पद कारण गढ़ते हैं जिनका यह सदन अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुये समर्थन नहीं कर सकता । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में क्या हो रहा है ? राजस्थान में कितने मंत्री नये बनाये गये ? विरोधी दलों के सदस्यों को लोभ से, लालच से, भय से आतंक से अपनी ओर तोड़ कर राजस्थान की कांग्रेस जिन मंत्रियों की बरात और जुलूस निकाल रही है यह बरात देख कर राजस्थान के राज्य-पाल को संविधान के प्रावधानों की याद नहीं आती है राजस्थान में 34–35 मंत्री हैं । उसमें से दल छोड़ कर आये हुये

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

कितने हैं इसका भी गृह मंत्री महोदय विचार कर लें ।

एक माननीय सदस्य : उसमें मंत्री ज्यादा नहीं लिए गये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मिनिस्टर नहीं लिये गये हैं तो छोटे मिनिस्टर लिये गये हैं लेकिन मंत्री बनाये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है किसी मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं यह किसी मंत्रिमंडल को भंग करने का आधार नहीं बना सकता । राज्यपाल ने एक दूसरा भी कारण दिया है । राज्यपाल महोदय कहते हैं कि हरयाना में पार्टियां बदली जा रही हैं निष्ठाओं में परिवर्त्तन हो रहा है कौन किसके साथ है यह कहना मुश्किल है । उनके शब्द यह हैं :

> "With such large scale and frequent defections, it is impossible to find out whether the will of the majority in the legislature does really represent the will of the people."

जनता की राय क्या है इसके निर्णायक राज्यपाल बनना चाहते हैं । हरयाना के राज्यपाल ने मंत्रिमंडल से यह नहीं कहा कि विधान सभा में आप का बहुमत संदिग्ध है, आप विधान सभा की बैठक बुलाइए । पश्चिमी बंगाल में विधान सभा की बैठक बुलाने पर बड़ा तूमार खड़ा किया जा रहा है । पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री विधान सभा की बैठक 15 दिन बाद बुलाना चाहते हैं इसलिए पश्चिमी बंगाल में चुनी हुई सरकार को तोड़ने की चर्चा हो रही है । यह तेहरा मापदंड अपनाया जा रहा है । जनता की राय का प्रतिनिधित्व विधान सभा करती है । उस विधान सभा में किस का बहुमत है यह शक्ति परोक्षा से तय हो सकती थी । मगर राज्यपाल ने हरयाना के मुख्य मंत्री को शक्ति परोक्षा के लिए नहीं कहा । उलटे उनकी रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि हरयाना के मुख्य मंत्री ने विधान सभा की बैठक बुलाने के बारे में जो कुछ कहा उससे वह संतुष्ट हो गए । मैं उनके शब्द सामने रखना चाहता हूं :

> "It was at this stage that I suggested to the Chief Minister that he might convene an early meeting of the Assembly for a trial of strength. He, however, felt that the trial of strength should come after the by-election due on 3-12-67. As this was a reasonable proposition, I did not press my point."

हरयाना के राज्यपाल मानते हैं कि 3 दिसम्बर से हरयाना की विधान सभा की बैठक करने का जो मुख्य मंत्री का प्रस्ताव था वह उचित था इसलिए मैंने इस बात पर दबाव नहीं डाला कि बैठक जल्दी होनी चाहिए । हरयाना के राज्यपाल ने बैठक जल्दी होने के लिए दबाव नहीं डाला क्योंकि वह जानते थे कि शक्ति परोक्षण में गैर-कांग्रेसी सरकार को हटाना संभव नहीं होगा । इसलिए उन्होंने एक नया कारण गढ़ा कि लोग दल बदल रहे हैं । हरयाना में दल-बदल का जो नाटक हुआ है वह बड़ा दुखदायी नाटक है । लोकतंत्र के हर एक प्रेमी को उससे पीड़ा हुई है । लेकिन यह नाटक केवल हरयाना में नहीं हो रहा है । दल-बदल के आधार पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है । दल-बदल के आधार पर आज पश्चिम बंगाल की गैर-कांग्रेसी सरकार को तोड़ना चाहते हैं । क्या दल-बदल की प्रवृत्ति दल-बदल का दृश्य राज्यपाल को संविधान को स्थगित करने की मांग करने का अधिकार देता है ? दल-बदल एक राजनैतिक अस्वस्थ प्रवृत्ति है । इसका इलाज राजनीति में है, संविधान की हत्या करने में नहीं है । हरयाना में किसने दल बदला है ? किसने दल बदलने के लिए प्रोत्साहित किया है ? इसकी अगर हम चर्चा करें तो कांग्रेस पार्टी कोई बहुत अच्छे रूप और रंग में निखर कर सामने नहीं आयेगी । हम यह मांग कर रहे हैं कि दल-बदल की समस्या पर विचार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन होना चाहिए और इसके लिए

स्वस्थ परंपरा उत्पन्न की जानी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कानून भी बनाया जा सकता है और अगर कानून बनाने का कोई प्रश्न आयेगा तो हम उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार होंगे। संविधान में संशोधन कर के दल-बदल को रोकने का प्रयत्न हो सकता है। आवश्यक हो तो चुने हुए सदस्यों को वापस बुलाने की व्यवस्था भी संविधान में की जा सकती है। लेकिन जब तक संविधान इस बारे में मौन है और संविधान में संशोधन करने का कोई ठोस सुझाव हमारे सामने नहीं है, हम राज्यपालों को यह अधिकार नहीं दे सकते कि वह दल-बदल का बहाना बना कर लोकतंत्र का गला घोंटें किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को अपदस्थ करने की सिफारिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय मुझे हरयाणा के राज्यपाल पर दया आती है। अभी तक मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि यह चौंकाने वाला निर्णय उन्होंने कैसे लिया। चर्चा हो रही थी पश्चिम बंगाल की और बज्रपात हुआ हरयाना के ऊपर। शायद हरयाणा में लोकतंत्र की हत्या कर के पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सत्तारूढ़ करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक चौंकाने वाला समाचार समाचार-पत्रों में आया। राज्यपाल ने रिपोर्ट दे दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि राज्यपाल की रिपोर्ट 17 नवम्बर की है मगर यही हरयाणा के राज्यपाल 30 अक्तूबर को क्या कहते हैं यह मैं आप के और सदन के सामने रखना चाहता हूं। दल उस समय भी बदले जा रहे थे। उस समय राव मंत्रि-मंडल को विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए चुनौती दी जा रही थी। लेकिन राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं उनके शब्दों को आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं।

"Chandigarh, October 30.

The Haryana Governor, Mr. B. N. Chakravarty, told reporters to-day that Rao Birendra Singh is still commanding the support of the largest single Party and, therefore, there is no occasion for him to intervene."

30 अक्तूबर को कसौटी यह थी कि राव वीरेन्द्र सिंह के साथ बहुमत है मगर 17 नवम्बर को यह कसौटी बादल गई। यह मानते हुए कि राव वीरेन्द्र सिंह के साथ बहुमत है, हरियाणा के राज्यपाल ने अब दूसरे ढंग की सिफारिश कर दी। उस वक्त उन्होंने कहा था—

Mr. Chakravarti said, from his study of the situation he felt that Rao Birendra Singh was still the leader of the largest single party in the Assembly. 'Unless he ceases to be that, I am not required to do anything'.

जब तक राव के साथ बहुमत है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। राव के साथ बहुमत 17 नवम्बर को भी था तो फिर यह रिपोर्ट कैसे आगई। राज्यपाल ने अपना मत क्यों बदला? उन्होंने आगे और बात कही है—

The Governor added : 'I am not under any obligation to do anything unless it is shown that others have joined together and formed a coalition.' Under the circumstances, the Governor felt there was no occasion for Rao as yet to resign.

क्या 30 अक्तूबर को दल बदल नहीं हो रहे थे? अब राज्यपाल को 17 नवम्बर को इल्हाम हो गया कि शासन ठप्प पड़ा है संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। 15 दिन पहले राज्यपाल का मूल्यांकन अलग था और 15 दिन के बाद परिस्थितियां इतनी बदल गईं—बदली हुई परिस्थितियों के क्या सुबूत हैं? राव मंत्री मंडल को बहुमत का समर्थन प्राप्त था—राज्यपाल ने इस आशय की रिपोर्ट उस वक्त क्यों दी थी? उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल बड़े कानूनदां मालूम होते हैं, कम-से-कम 30 अक्तूबर से पहले मालूम होते थे—

The Governor cited a Canadian parallel and said, there the largest single party, though not having an absolute majority, ruled for two years.

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

हरियाणा के राज्यपाल कहते हैं कि अगर बहुमत नहीं भी है तब भी शासन चल सकता है। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल कहते हैं—बहुमत है या नहीं—विधान सभा में साबित करो। हरियाणा के राज्यपाल कहते हैं—विधान सभा की जरूरत नहीं है शासन ठप्प हो गया है संविधान टूट गया है। इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि राष्ट्रपति राज्य लागू कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन भारतीय लोकतन्त्र में एक काले दिन के रूप में याद किया जायेगा, आज गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने के उपावलेपन में केन्द्र सरकार संविधान की अवहेलना के मार्ग पर कदम रख रही है। राजनीतिक लड़ाई में थोड़े काल के लिये विजय प्राप्त करने के लिये लोकतन्त्र की भावना का हनन कर रही है। राज्यपाल कोई गलती कर सकता है लेकिन केन्द्र सरकार को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिये था। मैंने प्रारम्भ में कहा था और मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि केन्द्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर सकती थी, राष्ट्रपति को सलाह दे सकती थी कि अभी हरियाणा में सरकार तोड़ने और विधान सभा भंग करने का समय नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय चुने हुए प्रतिनिधि अगर गलत आचरण करते हैं तो क्या जनता को चुने हुए शासन से वंचित कर देना चाहिये। हरियाणा की जनता को किस बात की सजा दी जा रही है। केवल कांग्रेस पार्टी कटघरे में नहीं है। केन्द्र सरकार भी कटघरे में आ गई है। मैं उन निष्कर्षों को पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता हूं जिनमें हरियाणा के राज्यपाल ने कहा है कि अपोजीशन ने, कांग्रेस दल ने ठीक आचरण नहीं किया। ठीक आचरण कांग्रेस दल ने नहीं किया, ठीक आचरण अन्य दलों ने नहीं किया तो इसका इलाज एक ही है कि संविधान में जिस बात की व्यवस्था की गई है कि संकटपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए उसका उपयोग किया जाये। हरियाणा में राज्य और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है हरियाणा में देश की एकता और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा में कानून और राज्य चल रहा है अगर ऐसा है तो समस्या राजनीतिक है और उसका हल राजनीतिक स्तर पर होना चाहिये। संविधान को खिलवाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मगर केन्द्र सरकार ने संविधान को खिलवाड़ बना कर आज लोकतन्त्र के लिये एक बड़ा भारी दुर्दिन पैदा किया है। हो सकता है कि इससे हरियाणा की गैर-कांग्रेसी सरकार टूट जाये मगर देश में अलोकतान्त्रिक शक्तियों को बल मिलेगा, संविधान के अन्दर रह कर कार्य करने वाले निरुत्साहित होंगे और सत्ता के लाभ ने केन्द्र सरकार को ऐसा पाप करने का दोषी बनाया जिसका कलंक उसके माथे से कभी नहीं छूटेगा।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I beg to move :

"That this House approves the Proclamation issued by the President of India on the 21st November, 1967, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Haryana."

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Murder of democracy.

SHRI Y. B. CHAVAN : This motion is a constitutional requirement, because after the Proclamation of the President taking over the administration of any State is issued, this motion has to be approved by Parliament if the Proclamation is to be effective after two months or so.

I am not going to reply to the points that Shri Vajpayee has raised, because that is a separate motion. I think I have got a right of reply to that some time, a little later. Naturally I will have to intervene in the debate, because it is a rather unusual debate that we have started.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : On a point of information. Have we got two debates or one debate ?

MR. DEPUTY-SPEAER : Two motions have been placed before the House, and he has the right to reply as well as the Mover.

SHRI Y. B. CHAVAN : This report of the Governor is on the political situation in Haryana, which I think any person who has got the cause of democracy at heart will study with care not merely from the point of view of a political party but from the point of view of the party system.

I know this is a rather exceptional step that the Governor had to recommend, and it is certainly after very careful consideration and great anxiety and unhappiness, that we had to accept this recommendation of the Governor. It is not a matter of happiness, but it is much better to see the facts as they are.

The situation in Haryana is this. The first Government was formed after the elections on 10th March. Immediately, within eight days, that Government was voted out, and, as a matter of fact, the leader of the Congress Party, who was then the Chief Minister, gracefully left office, and a new Government came in.

This matter of defections is certainly a new phenomenon in Indian politics.

AN HON. MEMBER : Why new ? It is old.

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara) : The Congress started it.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : 1952, Madras.

SHRI BAL RAJ MADHOK (Delhi South): Two-way traffic is new. One-way traffic was already there.

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर) : बगल में देखिये बगल में।

SHRI K. ANIRUDHAN (Chirayinkil) : Why do you say it is a new phenomenon ?

SHRI V. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore) : They started, we are following.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When Mr. Vajpayee moved his motion, there were many occasions for provocations from this side, but there was complete silence. Therefore, I request Members to be silent.

15.00 Hrs.

SHRI Y. B. CHAVAN : There may have been individual defections and crossing of the floor, but organised defection of this size certainly is a new phenomenon in Indian politics.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : संगठित तौर पर आपने महाराष्ट्र में करवाया था।

SHRI Y. B. CHAVAN : I can understand the defections to a certain extent, because at a certain stage, somebody may think that he can go from this party to the other because he believes in the programme and ideology of other parties. (*Interruption*). But the organised defections to become Ministers and Deputy Ministers and Speakers (*Interruption*) are strange. I can very well understand, and I can even go to that length and concede that if somebody goes and becomes a member of the other party to become a Minister, he must have the honesty to remain in that party at least. We have got instances in Haryana—

श्री मधु लिमये : मतलब एक डिफेक्शन अच्छा है दो अच्छे नहीं हैं !

SHRI Y. B. CHAVAN : There is some limit. There are some people who have crossed the floor four times. I need not read the whole report to make you aware of this because it is now the property of everybody here. It makes a rather tragic reading the way defections take place. (*Interruption*).

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why did you admit them in the party ?

SHRI Y. B. CHAVAN : In the report, the Governor has not spared any one party. I am not holding any brief to any party, and we (*Interruption*), have accepted the Governor's report. Just as he has criticised the party in power, the Governor has also criticised the party in the opposition also. And certainly it was his duty to say

[Shri Y. B. Chawan]

exactly what was happening. At least one para may be quoted, in which he has described the situation. He says :

> "In an Assembly with an effective strength of 79, some 30 members have defected one way or the other. Some members have defected not once but even three or four times. Two members have defected four times, two members thrice, and six members twice. To some members, changing the party is apparently of as little consequence as changing a coat. With such large scale and frequent defections, it is impssible to find out whether the will of the majority in the legislature does really represent the will of the people."

Certainly, we have to take into account the whole position. The hon. Member, Shri Vajpayee, while moving his motion, asked what was the position of the people in this whole thing. I must say that those parties or those members who went to the people to get their verdict in this matter have practically cheated the people. The people really do not know to which party their representatives belong, to what programme they are committed and what is the behaviour of those representatives going to be the next day. They do not know it. The course which the Governor has recommended to the President affords one more opportunity to the people, because the Governor has also recommended that after a brief period of President's rule, there may be another fresh election so that the people may take steps to see who their real representatives should be. (*Interruption*). It is not a question of President's rule for any length of time.

श्री मधु लिमये : हां तो मुख्य मंत्री को क्यों निकाला ? उनके रहते हुए चुनाव हो सकता था ।

SHRI Y. B. CHAVAN : When this type of defections go on taking place, what happens then ? Have the hon. Members tried to think about this particular problem? The officers do not know who their Ministers are going to be and what their policy is going to be.

SHRI RANGA (Srikakulam) : So is the case here.

SHRI Y. B. CHAVAN : As far as th administration is concerned, it has come to a standstill, and consequently democracy has become a mockery in that State. Naturally, the Governor had to take up this basic position into consideration and make up his own mind. Naturally, when he was speaking on the 30th October, the question before him was the same—the points that the hon. Member was referreing to—the reply to the points made out by the Opposition, who wanted to be the stable government. He made a proposition of calling the Assembly to the Chief Minister, to which he said, sometime in December it could be called. He accepted it. But when later on also he saw that tendency of defection—one person joins the party, becomes a minister and within a few hours he again comes back—he was wondering, even if there is a majority Government of 3 or 4, who are the invisible defectors on each side. One does not know.

AN. HON. MEMBER : Who is the Governor ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Governor is the Governor.

AN. HON. MEMBER : Governor has defected. (*Interruptions*).

SHRI Y. B. CHAVAN : I think the minds of some of the members are defecting here also. (*Interruptions*).

The Governor, after careful consideration, came to the conclusion that Government, according to the Constitution, was impossible. Let us not make a mockery of majority and minority. Certainly there should be a majority, but here really speaking, the relationship between the representatives of the people and the people themselves has completely broken down. Therefore, the will of the people was not represented in the present composition of the legislature as it functioned. Unfortunately, it is a fact. Therefore, the Governor had to take cognizance of this extraordinary political situation in the State. When he has to do that, the Constitution has to be interpreted with the political assessment of the situation in the State. He certainly assessed the political situation in a particular way and recommended to the President to take over the administration of the State.

As I said, it was not a matter of happiness for anyone. The report came before us on the 17th of this month. We carefully considered the pros and cons of the situation. It was with unhappiness and reluctance that we had to come to this conclusion. It is not a pleasant duty to take over the administration under President's rule. Independently of the Governor's recommendations, even some eminent members of the opposition came to their own conclusion that President's rule should be established. I am not asking an explanation. If he has changed his mind, he has a right to change his mind. Normally they change their mind when we take a decision. The hon. member, Mr. Sondhi, who can be considered to be the brain-trust of the Jan Sangh had made this statement. It is not something very extraordinary that the Governor thought of it. He was watching the situation from day to day. He naturally had the responsibility to make an assessment and he made that assessment. His recommendation to the President was based on that assessment and this Government has agreed with that. Therefore, we advised the President to issue the proclamation.

Sir, I would commend this Resolution for the acceptance of this House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Both the motions are before the House.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Sir, if anything is needed to condemn the present Home Minister as the hangman of India's democracy, this action which he has taken is enough. My hon. friend was talking about democracy being made a mockery in this country. While he was saying that, I was reminded of what was happening in France, when de Gaulle was taking charge of that administration. There cannot be any de Gaulle here because most of these gentlemen do not even have the claim that de Gaulle has had in standing up for the freedom and liberty of his country during the last war. Here are these gentlemen who have led the way for these defections—not for ideological purposes. Some of my friends might not agree with me, but I do feel that Shri Ashoka Mehta had left his party for ideological purposes—but only not for those purposes, as he put it and for ministerial possessions in the bargain.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : You are in the same category.

SHRI RANGA : What is it that the present Home Minister is doing ? What is it that he has done when all those things were being done in Rajasthan under his protection, with his blessings and, possibly, with his secret advice ? Why did he not then advise that Governor, as he has been advising so many other Governors ? Why did he not get that Governor dismissed when he misbehaived in that shameless manner in order to prop up this Congress Party and its murderous attacks on India's democracy ? At that time it was all very sweet, as sweet as *rasagulla* and therefore he swallowed it. But when it comes to Bengal it is not so sweet because Bengal is the real home of *rasagulla* and that *rasagulla* has proved to be poison for my hon. friend.

I thought we were meeting here today in order to hear him say that Bengal Government is dismissed. But, no, it is the Haryana Government. Why ? It is because he finds a devil for him, equal in its manoeuvres, in its unscrupulousness, ini ts anxiety and haste to dismiss, destroy and demoralise democracy as the Congress Government has proved itself to be. It has met its own match there and it is afraid of touching the Bengal Government. As I was reading this report I thought that my good old friend, Shri Dharam Vira, the Governor was writing this. But it is not so. It is Governor Chakravarty who has written this report. That Governor has not had the moral courage nor has this Home Minister got it. I would have understood if this Home Minister had resigned yesterday and a new Home Minister had presented it today. But the same Home Minister has the ignominy of carrying on his flirtations with the Bengal Government and dismissing this Government here. He says this Government is so very bad that there cannot be any stable Government here in Haryana. Has there been any stable government in Bengal for the past so many weeks, so many months ? What has he been doing ? What has my hon. friend, the champion of democracy done ? He should have dismissed it at the time of Naxalbari. He should have had that moral courage even during the period when the Labour Minister and the Home Minister

[Shri Ranga]

there were trying to fasten their gheraos over law abiding people in Bengal. Did he have that moral courage? No. He is now trying to fasten and sharpen this weapon of defectons in Bengal. He has already got one set out. He is trying to pitchfork one of them and put him as the Chief Minister. Is he going to have a stable government after dismissing the present so-called SVD Government in Bengal? No. I would have been very glad indeed if my hon. friend Dr. Ghosh were to become the Chief Minister there. He should have been the Chief Minister all these years because he has been known to be the most honest Congressman who has ever attained the position of a Minister. It was because he was the most honest Congress Minister—and it was accepted even by the respected *Statesman*, the daily paper—that he was dismissed by his partymen, Congressmen, after six months of his ministerial regime. Now they are anxious to pitchfork him into Chief Minister. Why? Becuase they cannot get anyone of their own partymen. Why? Because, their partymen have become demoralised, discredited and they have been known to be dishonest in the whole of Bengal, if not in the whole of India. This is the sordid story of the achievements of this Congress under this Home Minister. I am extremly sorry for him, Shri Chavan, because he has allowed himself to be shifted from one Ministry to another. He thought that this was a promotion for him. Some of his friends also thought that this was a promotion for him. Instead of fighting the Chinese demon, he has come to fight our own democracy. Instead of driving the Chinese out, now he is driving our own Ministers from their seats. This is his only achievement.

He has been known as the great hero of Sahyadri. He has come over to Himachal. Now what ice and what snow is he going to find at the Himalayas, God only knows. But I know that he has earned this unenviable title of the hangman of India's democracy.

He says he cannot wait until the Haryana Assembly meets. He must forthwith dismiss this Ministry. Therefore, he has dismissed it. That Ministry, unfortunately for him, has played into his hands. It has over-played their own game, the Congress game of defection. They have made it a science. Rao Birindra Singh has proved to be a better master of science than their own leader, Shri Sharma, who was in power there, and his new ally, Shri Devi Lal. What a Devi Lal and what a Sharma! This is a country of Devi Lals and Sharmas. These two have played themselves into the hands of this Home Minister and made it so very convenient for him to come here in this House. But I accuse this Congress not only for having started the game but for continuing it and for having made it into such a fashionable political weapon that today the Governor of Haryana is obliged to say that he cannot be sure of any kind of a stable majority from any group. And the Congress Opposition never accepted its position as Opposition. Shame to these friends here sitting in these benches over there. Shame indeed. They want to pose as champions of democracy, as practitioners of democracy. But when they find themselves in a minority, they do not have the decency, the common decency, to put up with the other group remaining in power. They must go on working day after day, in a nefarious manner, in a shameless manner, in order to wean away more and more people. How many times Devi Lal has made his pilgrimage to this *Dam* here How many times he has made not only his pilgrimage but offered his *salams* to the Home Minister? What plans they have made between them, what schemes they have hatched between them, God only knows, but the result we know. This is the achievement my friends have got. Are they proud of it? Should they be proud of it? Let them place their own hands on their own hearts and say to themselves whether they can be proud of the game they have played, of the role they have played on India's democracy in this manner.

This Ministry is going. I do not regret it. I do not also regret that this Assembly is going. But I do regret the manner in which they are sent away, in this discriminatory fashion, while that Assembly is kept alive, and that Ministry is kept alive and their Governor is expected to reamain by the phone, the hot phone between Calcutta and Delhi, only to know the mind and the doings of these two great persons, the Prime Minister and the Home Minister.

I do not know the other members of their so-called internal committee. What is the role of this internal committee? Is it to provide for us stable democracy in our country ?

My. hon. friend says that the legislators in Haryana would not know or did not know who is a minister today, who will not be a minister tomorrow and who was the minister yesterday. But what is happening in this House itself ? The other day first of all three, then a fourth, then a fifth and now, how many, six Deputy Ministers were sworn in and the portfolios were all re-organised, of the old ones as well as of the new ones. As if this is not enough, the Prime Minister must add on to herself new *saris* of new portfolios.....(*Interruption*). Do we ourselves know which portfolio is held by each of these gentlemen here ? These very fair faces are all very pleasing to us to see but their doings are not pleasant to us at all.

This is a disease that has overtaken the Congress. It is such an infectious disease that it threatens to overtake the Opposition also, with the result that the whole of democracy in India is in danger of being destroyed. Only one group comes out with flying colours and that is the Jana Sangh of Haryana. They had 10 Members, I suppose and they had the decency, the decorum, the character and the integrity to refuse to accept any ministership. They have remained true to their profession during all these eight or nine months while all others were running after these ministerships in this manner. What is the bird that runs after these various things in such a disgusting manner ? It is the crow among the Indian birds. That is the role that is being played by them. By whom ? Most of these defectors were erstwhile Congressmen on this side or on that side. My hon. friend says that some of them have changed three times, some four times and some even five times. This is the legacy that is being presented to this Indian democracy by this Congress Party which has remained continuously in power here at the Centre for all these 20 years and in that State also for such a long time.

One cannot be proud of such a brood; one cannot be proud of such a breed and the time has come that this brood and this breed should go. And they would go. They have produced this demon of defection. Only the other day I saw a picture an excellent picture, in Telugu of *Krishnavatara*. At the end of the whole of the story of Krishna, one male Yadava warrior began to suffer from birth pangs. Then, he gave birth to *Musala*. That *Musala* was turned into dust by the drunken Yadavas and with that dust, they fed the plants. With those plants they killed themselves. That is the *Musala* that the Congress Party has bred. These are the plants that they have planted in all the States and with those plants they are going to destroy themselves. But in the bargain the country will be destroyed, India's democracy will be destroyed, India's freedom will be destroyed, India's Chapter on Fundamental Rights will come to be destroyed. That is why I condemn this Ministry, I condemn this Government, I condemn this Home Minister.

But I have a word of commiseration for Shri Chakravarty, the Governor. He is only made the mere instrument of their oppressive act that they have done, but the note that he has prepared is certainly one that does not do any discredit to him.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : माननीय डिप्टी स्पीकर साहब हरयाने के बहादुर 76 लाख इन्सानों के लिए जो बेहतरीन हिन्दुस्तान के किसान हैं जो बेहतरीन हिन्दुस्तान की फौज के सिपाही हैं बेहतरीन हुब्बलेवतन हैं उनके लिए आज का दिन एक नजात का दिन है। आज का दिन दीवाली का दिन है और मुझे ताज्जुब होता है मैं बड़ा आदर करता हूं अटल भाई का और बड़ा आदर करता हूं रंगा जी का। मैं जानता हूं उनको बड़ा प्रेम है हरयाना के साथ लेकिन यह क्या हो गया ? यह हुआ क्या 24 घंटे में ? यही आदमी जिन्होंने मेरे कपड़े फाड़ लिए जो मुझे लाबीज से गुजरने नहीं देते थे कहते थे हरयाने का यह क्या हो रहा है ? वही लोग आज जो कुछ हरयाने में हुआ उसको जस्टिफाई करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब हम तो समझते थे कि नथिंग कैन बीट दि करेज आफ ए लाइयर लेकिन यहां तो उलटा है—नथिंग कैन बीट

[श्री रणधीर सिंह]

दि करेज आफ दि अपोजीशन हियर यह हम देख रहे हैं। जो अपने आप को लीडर कहते हैं उनका यह हाल है। मैं चाहता था कि इस हाउस की तरफ से इस मामले में यूनेनिमसली हरयाने के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को होमेज पे करना चाहिए था। · · · (**व्यवधान**) · · ·

डिप्टी स्पीकर साहब यह वह हरयाना है जिसने सन 1857 में सब से पहले अंग्रेजों से लोहा लिया और यह वह हरयाना है जिसने सन् '42 के करो या मरो की लड़ाई में सब से आगे बढ़ कर भाग लिया और सारे के सारे हिन्दुस्तान में 50 हजार आदमी जेलों में दे दिए। यह वह हरयाना है जिसने चीनियों के खिलाफ युद्ध में ब्रिगेडियर होशियार सिंह और मेजर जनरल बुध सिंह जैसे जनरल दिए और उसी हरयाने ने · · · (**व्यवधान**) · · ·

डिप्टी स्पीकर साहब मुझे हमदर्दी है अपने भाई से। देखिए मधोक साहब का कुनबा इनके साथ में नहीं है। मुझे बड़ा रहम आता है इनके ऊपर। उनके पीछे हमारे सोंधी साहब बैठे हैं। सोंधी साहब का कल का स्टेटमेंट है उसका मुलाहिजा फरमायें। रोहतक तशरीफ ले गए थे। वहां से दिल्ली आते ही कहा कि हरयाने में मुझे शर्म आई। गवर्नरी रूल वहां होना चाहिए। · · · (**व्यवधान**) · · · यही नहीं मेरे फाजिल दोस्त यज्ञदत्त जी शर्मा बैठे हैं लाखों में एक आदमी हैं हीरा हैं। एक बार नहीं दस बार कहा है इन्हीं यज्ञदत्त शर्मा जी ने कि मुझे शर्म आती है हरयाने में जो हालत है उस पर। यही नहीं कृष्ण लाल शर्मा इनके जनसंघ के सेक्रेटरी हैं पंजाब के और हरयाना के। उनका स्टेटमेंट है वह कहते हैं कि हमें शर्म आती है हरयाने में जो कुछ हो रहा है उससे। इनके ही एम० एल० ए० जनसंघ के श्री प्रभाकर ने जो कुछ कच्चा चिट्ठा वहां का सुनाया है उसे आप सुनिए। इनके साथी इनके कब्जे में नहीं हैं। मेरे भाई अटल बिहारी वाजपेयी और मेरे निहायत लायक दोस्त मधोक साहब के साथ उनकी पार्टी नहीं है। यह हालत है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हो रही है। इनकी पार्टी वाले हरयाने के कहते हैं कि हरयाने का जो ड्रामा है वह शर्मनाक है देश के नाम पर यह कलंक है और यह खत्म होना चाहिए। यही नहीं जिसका मुकदमा यह थाम्हे हुए हैं चीफ मिनिस्टर राव वीरेन्द्र सिंह, मैं लाइयुर हूं एक-एक बात लिख कर लाया हूं। उनका सब का जरा मुलाहिजा फरमाइए। एक-एक का मैं नाम लेता जाऊंगा। राव वीरेन्द्र सिंह का स्टेटमेंट जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ता० 18 और 11वें महीने का है। प्रताप अखबार निकालिये और उसका सफ़ा 2 निकालिये उन्होंने विलासपुर में कान्फ्रेंन्स की और इस बात को माना . . .

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Will you please request the hon. Member to speak less loudly so that we may be able to understand what he is saying.

श्री रणधीर सिंह : 40 साल तक हरियाणा की भूरी भैंस का दूध पीया है। मैं हरियाणा के किसान का लड़का हूं मरा हुआ आदमी नहीं हूं। 40 साल घी खाया है प्योर घी खाया है।

मैं अर्ज कर रहा था, डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो लायर हैं, इस लिये आप जानते होंगे कि जिस लायर ने खुद मान लिया हो कि मेरा मुकदमा कुछ नहीं है, वह मुकदमा क्या चलेगा। इस वीरेन्द्र सिंह ने खुद माना है; मैंने उसके कन्फेशन का हवाला दिया है कि क्या हुकूमत चलाऊं, इस हुकूमत में तो लोग डंगर-भेड़ों की तरह बिकते हैं, कीमतें मुकर्रिर होतीं हैं, एम० एल० एज़० की—10 हजार, 15 हजार, 20 हजार रुपये। जैसे भेड़ें नीलाम होतीं हैं, हरियाणा में एम० एल० एज़ नीलाम होते हैं, मुझे शर्म आती है। मेरे दोस्त और मेरे लीडर कृपलानी जी ने, जिनका मैं आदर करता हूं, जैसा कहा कि यह जज़बात नहीं खुद्दारी का मामला है। मैं तो केन्द्रीय सरकार पर इल्ज़ाम लगाता हूं कि वह क्यों इतनी देर तक चुप बैठी रही, तीन महीने पहले इनको डिसमिस करना

चाहिये था, इनको जेल में डालना चाहिये था, कमीशन मुकर्रिर करना चाहिये था, इनके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिये था और मैं पूरी जिम्मेदारी से होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि इन लोगों ने लाखों रुपये कमाये हैं एक-एक रात में, इन लोगों ने किसानों का 15–15, 20–20 रु० मन का अनाज 70–70 रु० मन में बिकवाया है और एक-एक वजीर ने 10–10, 15–15 लाख रुपया कमाया है। यह बात सही है, जरा कमीशन मुकर्रिर होने दीजिये, और भी बहुत सी बातें निकलेंगी। एक तरफ़ हमारे बहादुर सिपाही बार्डर पर देश के लिये लड़ते हैं, देश की इज्जत को बचाते हैं, 67 रु० में जाकर मरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ़ उनके ये नेता नीलामी पर बिकते हैं डंगरों की तरह बिकते हैं और फिर यहां उनकी सराहना की जाये, मुझ शर्म आती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां एक लक्ष्मण सिंह हैं, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर—उन्होंने भी कहा है ···

श्री यज्ञदत्त शर्मा (अमृतसर) : वह कांग्रेस के आदमी हैं।

श्री रणबीर सिंह : उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है कि गिरदावर बनना मुश्किल है, लेकिन वजीर बनना आसान है। इसी तरह से एक और मिनिस्टर साहब को लीजिए ये मिनिस्ट्री में नं० 2 या 3 हैं, बीरेन्द्र सिंह के आदमी हैं, इनका नाम है—मूल चन्द जैन, जिसको आपने डिसमिस किया है। ये भाई यह कहते हैं—मुझे शर्म आती है—लेकिन उनका स्टेटमेन्ट मुलाहज़ा हो—3–11–67 हिन्दुस्तान टाइम्ज, बैनर हैडलाइन्ज—"मुझे शर्म आती है जो हाल आज हरियाणा का है, इससे अच्छा तो गवर्नरी राज है। इस असेम्बली को तोड़ा जाये और इलैक्शन्ज दोबारा हों।" यह मूल चन्द जैन ने कहा है जो इस मिनिस्ट्री के चांसलर आफ़ एक्सचेकर हैं और बीरेन्द्र सिंह की नाक के बाल हैं।

अब उसको लीजिये जो इस मिनिस्ट्री का ब्रेन-ट्रस्ट है, दिमाग है—हरद्वारी लाल, जो संत बन गया है। वह कहते हैं कि मैं तो संत हो गया हूं—बड़े बहरूपिया बनते हैं। वह फरमाते हैं—मेरी तो ज़मीन बैठ गई है—कोई भी मिनिस्टर बन जाता है, मतलब क्या है? मैं तो भागना चाहता हूं, लेकिन भाग कर कहां जाऊं—उसको सपोर्ट करते हैं अटल भाई। वह कहते हैं कि यह हुकूमत टूटनी चाहिये, इस हुकूमत का मिनिस्टर बनना बेइज्जती है।

आगे प्रताप सिंह दौलता क्या कहते हैं। मैं जब यहां से गया दर्वाजे से आगे, तो बैठे हुए मिले आध घन्टा पहले, एन मौके पर अदालत में गवाह बैठा है, वह सुन रहा है। वह कहता है—शानदार दिन इस गवर्नमेन्ट के लिये आ गया है। हर तीसरे दिन खाने के पहले कोसता था। वह वज़ारत को कोसता पहले था—सोते कोसता था; बैठते कोसता था, जागते कोसता था, खाते कोसता था। मैं अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जो उसने इस्तेमाल किये—"ऐसे उल्लू के पट्ठे कोई नहीं मिलेंगे।" वह बार-बार कहता है और रोहतक की मीटिंग में भी उसने कहा था—"ये मिनिस्टर उल्लू के पट्ठे वे लोग हैं, जो किसी के बस के नहीं हैं।" यह अपनी मिनिस्ट्री के लिये उसने कहा। "असली उल्लू मिनिस्टर बनाये जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं।"

यह ही नहीं, एक-एक बात उसकी नोट फरमाइये। वह कहता है कि हमें सज़ा मिलनी चाहिये ···

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : How far is it parliamentary to use phrases like 'Ulloo ke pathe'.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is only quoting from some statements. (*Interruptions*).

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Sir, you should also see that some relevance is maintained in his speech. It is only bellowing, screaming and howling.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would very much like both sides to observe the rules of relevance. But, unfortunately, it is not being observed and I am very sorry for it.

श्री रणधीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, एक फ्रेज़ है—

The man who has lost his case must fight.

जो आदमी मुकदमा हार जाता है, वह लड़ता है। ये मुकदमा हारे हुए हैं, इस लिये लड़ना चाहते हैं।

मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वह यह है कि उस प्रताप सिंह दौलता ने यह कहा है कि मुझे सज़ा देनी चाहिये जनता को। मैं चाहता हूं कि जनता मुझे सज़ा दे और मेरे साथ दूसरे मुलज़िमों को भी सज़ा दे कैबिनेट के। इस कैबिनेट को चलने का कोई हक़ नहीं है। यह उसकी स्पीच है, अखबारों में, एक दर्जन बार उसने अपनी स्पीचों में कहा है—हमने जुर्म किया है, हरियाणा के साथ हमने बड़ा अत्याचार किया है और उसकी वजह से हम कोई फायदा हरियाणा का कर नहीं रहे हैं, इसलिये हमको सज़ा मिलनी चाहिये।

एक कैबिनेट मिनिस्टर और हैं—नये मुसलमान बने थे—श्री राजिन्द्र सिंह जी जो 10 दिन हुए बज़ारत में गये थे। वह मिनिस्टर बन कर अपने हल्के में आये, उन्होंने गनानौर में आ कर तकरीर की, उनकी वह स्पीच पढ़ने लायक है, चूंकि वक्त नहीं है, इसलिये मैं डिटेल में नहीं जाता हूं।

मैं कहना चाहता हूं, चव्हाण साहब, मुझे आपसे यह शिकायत है कि आपको यह बहुत पहले करना चाहिये था। फिर भी मैं आपको हरियाणा के जो 76 लाख, 80लाख बहादुर सपूत हैं, किसान-मजदूर हैं, 36 बिरादरियों के, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता हूं, उनकी तरफ़ से बधाई देता हूं। उनका जो रेजोल्यूशन है मैं उसकी मुखालिफत करता हूं और आपने जो रेजोल्यूशन पेश किया है, उसकी पुरज़ोर हिमायत करता हूं।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I rise to a point of order and it is this. I would invite your attention to rule 356 which reads thus :

> The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or intedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech.....

You should have taken recourse to this rule.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have seen that rule already. The same rule was pointed out to me earlier by Shri S. Kundu, and immediately I had requested the hon. Member to conclude and he has now concluded.

SHRI S. M. BANERJEE : You should have sent him out.

SHRI RANDHIR SINGH : What is this ? It is a question of give-and-take.

SHRI S. KUNDU : During this time, the hon. Member Shri Randhir Singh has caused serious damage to our ear-drums by shouting in this manner. We do not know who will compensate us for this.

SHRI RAJARAM (Salem) : The Haryana Member, because he is lonely here from the Congress Party from Haryana has shouted in this manner to establish his case.

SHRI RANDHIR SINGH : I was not shouting. That was the strong voice from my innermost heart.

SHRI RAJARAM : Even in that shouting, he has said a very good thing; he has paid homage to the Central Congress Government because the day is not far off to pay homage to the Central Government. As far as Haryana is concerned, today is the blackest day in our country. The Congress Party has ruled this country for the past twenty years or so in a non-stop manner and has ruled all over the States. But even after twenty years of rule, they do not know how to establish democracy in this country. Unexpectedly, the Congress Party got hold of the Central Government and through

that they are now wanting to bring to a collapse the non-Congress Governments in all the other States. Now, the day has dawned for this at Haryana. Even the common people in the villages know that the Central Congress Government are running with a dagger towards the Bengal Government to kill democracy in Bengal. But unexpectedly, they have killed democracy in Haryana, and see how nicely, how coolly and how silently they have done it. The biggest murderer of democracy in Haryana is the Central Congress Government.

The Home Minister has stated several points in his speech. He has even approved the defections. He pointed out that somebody became a Minister in Haryana and within five days he resigned his Ministership. For everything there is a precedent in India. In the Madras State, when the Justice Party ruled in those days, under dyarchy under the British regime, a member became the Law Minister but he resigned that post within three days. Even then, the Britishers did not act so viciously, so maliciously, so badly or so shamelessly against that Government, but now this Government has acted in such a manner.

I am now thinking about Haryana because Haryana is the base of democracy, it is ruled by an opposition party. Even according to the Governor's letter, the last words say :

> "Until there is such defection, Rao Birendra Singh still commands the majority of party members in an effective House of 78."

Even if there is a majority of one or two members, that is enough. You are here to safeguard that Government, you are here to run democracy all over the country. You wanted to teach the ideology of democracy to the masses, but what will the common man think about us if you bring about the collapse of a Government by such a kind of backdoor method, if you bring President's rule all of a sudden without any notice. What will the common man in the village and in the city think ? He will lose faith in democracy. Military rule may come in India, and it is going to come if you act like this all over the States.

The opposition have begun to rule only in the last ten months. In these ten months, somebody has established a very fine rule, somebody has trouble with his ministry, somebody is loitering hither and thither. What is the harm ? Why don't you give them enough time to strengthen themselves? Even if it is a one vote majority, you must accept it.

As far as defections are concerned, who has taught it to us ? In 1952, when Madras turned against the Congress Government, what happened ? The *ex*-Food Minister, Shri C. Subramaniam, the *ex*-Deputy Education Minister, Shrimati Soundaram Ramachandran, and all the other Congress people rushed to Delhi to meet the great democrat, Pandit Nehru. Then they returned to Madras, they defected other party members and formed the Government under the able leadership of Rajaji, and he has been praised like anything for causing this defection.

It is rightly said that consistency is the virtue of an ass. So, consistency is not growing in this country. What is wrong with defections, if something is going on here and there, there is nothing wrong. But in Haryana you toppled the Ministry in no time. As the Speaker said this morning, he knew it only from the papers. If that is the case, the Congress Central Government is also going to see their fate only from the papers. That is the case they are going to establish in this country.

If this is the case of Haryana today, it will be the case of Bengal tomorrow. It may proceed up to Cape Comerin the day after tomorrow. We are not going to watch this game as silent spectators. We are the elected representatives of this country. We want to safeguard democracy in this country. So, our intention is to teach some lesson to this Home Minister or to this Central Congress Government, to act sensibly and act wisely. So, on behalf of our party, the DMK, we are supporting the adjournment motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is no adjournment motion before the House.

There are two motions simultaneously placed.

SHRI RAJARAM : I support the motion moved by Shri Vajpayee.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I do not think today is a very happy day either for the Congress or for the Members of the Opposition. In a parliamentry democracy, it is quite expected that some parties will come and some parties will go. It is in the natural course of events, and one should accept the change sportingly. Now that the Congress does not enjoy majority in so many other States, I do not think it should be so seriously disturbed because for 20 years the Congress had [carried on the government in all the States. A change for a while, through government of other parties, is not a matter to be worried about, and the Congress' turn will, I am sure, come again. That is inevitable in a parliamentary Democracy.

Now, let us see what has happened ? The political picture of Haryana, as it has been unfolding over the last few months, I am sure, has not been a matter of happiness or pleasure to anybody, any person who has any regard for democracy or for political honesty. In fact, the Members of the Opposition as well as Members of the Congress have been watching with amazement and bewilderment the happenings in Haryana, and in private talks all of us have been condemning whatever has happened there. I do not want to exonerate the Members of the Congress there either. Both the sides, and all the parties there have behaved in a way which is highly irresponsible. That only goes to show that they were not fit to carry on the administration there.

I do not wish to go into details of the letter of the Governor which has been extensively quoted by Shri Vajpayee, but I was trying to read it hurriedly and mark the number of changes that took place in the ministry since 10th March last. I have counted 17 changes—17 times, a new member comes or some change is made or a parliamentary secretary gets promoted as Minister or something or the other has taken place. This goes to show that in a most dishonest way, in a most cheap way, effort has been made by politicians to maintain themselves in power. I am sure that does not redound to the credit of any party. Some people have changed parties three times or four times; Mr. Arya has changed for the fifth time. Even while the Governor was writing his letter, four members came to say that they had changed their loyalties and become members of the Congress. I am not holding a brief for the Congress. I am condemning all the parties equally in Haryana; they have been so irresponsible that they are really not fit to be the representatives of the people or to hold the responsibility of government.

What is the purpose of the administration? What is the purpose of a government? Whether it is democratic or whether is any other form of government, whether it is proletarian or whether it is King's rule, the purpose of the administration is to administer. I would like to ask what kind of administration these members might have indulged in during the last few months? They were so busy securing chairs for themselves; they were busy in canvassing people, kidnapping people; if I may say so, snatching them and locking them up. They have been busy with intimadating their members. This was the work they were busy with. What kind of administration they were carrying ? When the Ministers were so preoccupied, I am quite sure that the bureaucracy was free to do whatever it liked. I am sure many things must have been done which were not proper. But the Governor, in his report, says that even the bureaucracy was not left alone. The party members were going on worrying the members of the administration, putting pressure on them for their transfers and for various such purposes. Therefore, the administration in Haryana had become a mockery. I would, with great humility, question my hon. friend Shri Vajpayee who appealed in the name of the people of Haryana that this must not be done and democracy must not be murdered. I would say that I am quite sure that the stalwart, strong people of Haryana—one of my hon. friends from Haryana was roaring like a lion—who swell the army, who are strong, virile and stalwart peasants, who are practical people and who know how to run their affairs, have now heaved a sigh of relief when this Ministry has gone.

What are the facts of the case ? Could the Central Government or for that matter anybody have interfered with the administration of Haryana if they had carried on the government well ?

The fault does not lie with the Governor. If they had carried on the government properly and given good administration to the people, nobody would have interfered. But they did not carry on the government in a proper way. It is no use blaming the Governor. You could have blamed him if he had tried to carry this on for a few more days, waited for the Congress to obtain a majority in the process of juggling of seats and handed over the government to the Congress. He did not do that. In his letter he says clearly that the Congress as well as the other parties have been behaving in an irresponsible manner and under those circumstances, his assessment was that stable government was impossible. He says :

"With such large scale and frequent defections, it is impossible to find out whether the will of the majority in the legislature does really represent the will of the people."

When that was the situation, how do we blame the Governor for giving this advice ? This flexible loyalty is most deplorable. I think the situation now obtaining in the politidal arena in India is lowering our prestige not only in our country, but also abroad. Everybody is watching with bewilderment as to what is happening here. There is an open allegation by all the parties that the power is being maintained by bribery, corruption, political victimisation, etc. In that state of things, I would ask my friends in the opposition, do they really honestly feel that this ministry should or could have continued and by throwing it out, democracy has been murdered ? I would rather say that the people of Haryana deserve a better administration. They do not deserve to see this kind of scandal. It demoralises them and frustrates them. Therefore, without going into the constitutional issues, I would say that all people in their heart of hearts are glad that this ministry has been dismissed. The people will now be given an opportunity to express their will after six months and I am sure those who come to power there, after six months will show a greater sense of responsibility and will give a better administration to the State having learnt a better lesson. That is why I support the resolution moved by the Home Minister.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से · · ·

कुछ माननीय सदस्य : कौन सी पार्टी ?

श्री स० मो० बनर्जी : कम्युनिस्ट पार्टी।

कुछ माननीय सदस्य : यह भी डिफ़ेक्टर हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : राष्ट्रपति जी ने जो घोषणा की है, मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उसकी मुख़ालफ़त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है :

"It is possible that when the news gets round that the Devi Lal group has merged with the official Congress Legislature Party, some members in the ruling party now sitting on the fence, may also defect. Until there is such defection, Rao Birender Singh still commands the majority of 40 members in an effective house of 78."

[MR. SPEAKER *in the chair*]

16 Hrs.

इस पत्र से साफ़ साबित हो जाता है कि आज भी, जब कि हरियाणा में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है, प्रजातांत्रिक असूलों के आधार पर चुनी हुई हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया है, जीते जी उस को दफ़न कर दिया गया है, हरियाणा विधान सभा के सदस्यों की मैजारिटी राव वीरेन्द्र सिंह के साथ है। इससे यह भी ज़ाहिर हो जाता है कि यह केवल हरियाणा का मामला नहीं है। गृह मंत्री ने और सत्ता की शराब में डूबी हुई इस केन्द्रीय कांग्रेस सरकार ने यह तय कर लिया है कि बंगाल में प्रजातंत्र की हत्या करने से पहले एक छोटी सी हत्या कर दें, ताकि लोग कहें कि हत्या करने में भी इन्होंने समाजवादी ढंग से काम किया है। यह नहीं कि आज हरयाने में सरकार रह गई और वहां की सरकार को उन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं यह समझता हूं कि आज अगर आप देखें डिफेक्शंस के बारे में बहुत सी बात कही गई। मैं पूछना चाहता हूं आज गृह मंत्री जी से कि जब हमारे योजना मंत्री जी या पेट्रो•

[श्री स० मो० बनर्जी]

केमिकल के मंत्री जी अशोक-मेहता साहब गए थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में तो उनको जब गले से लगा लिया था तो क्या सोचा नहीं था कि आखिर इसका क्या असर होगा ? हमारे देश में तो डिफेक्शन की परंपरा रामायण से चल रही है । विभीषण ने डिफेक्शन किया था । अगर आप देखें कि पहला डिफेक्टर कौन था तो मालूम होगा विभीषण ने डिफेक्शन किया था, वह आकर राम से मिल गए थे । इसीलिए मैं ने कहा कि कांग्रेस में जब इसी तरह से होता रहा तब तो इन चीजों को कहा गया कि नेकनीयती के आधार पर यह चीजें हो रही हैं । इट इज मौरल । और उसके बाद जब वह डिफेक्शन उनके गले का कांटा बन गया तो उन्होंने कहना शुरू किया कि यह इम्मौरल हो गया । मैं, श्री कंवर लाल गुप्त और कुछ और लोग अभी चीफ व्हिप्स कान्फरेंस हुई थी, उसमें गए थे । वहां मैंने देखा कि जहां जहां गैर-कांग्रेसी हुकूमत थीं वहां के कांग्रेसी चीफ व्हिप जो आये थे वह यह कहते थे कि रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट को बदल दिया जाय जिसमें यह डिफेक्शन न हो सके । हम लोगों ने एक ही जवाब दिया था कि डिफेक्शन के बारे में गहराई से और संजीदगी से तब सोचेंगे जब सेंटर में भी डिफेक्शन शुरू हो जाय । डिफेक्शन दिल्ली तक तो पहुंचे कम से कम तब मालूम हो कि डिफेक्शन क्या है । गवर्नर के पत्र को पढ़ कर यह साफ मालूम होता है आज भी बहुमत हरयाने की असेम्बली में राव साहब के साथ है । लेकिन एक राजनैतिक मकसद से यह देखा गया और सरकार को खत्म कर दिया गया । इसलिए कि उसके बाद बंगाल को खत्म करना है और बंगाल और हरयाने के बीच में बिहार जो है उसको भी खत्म करने की कोशिश की जायगी । अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता हूं कि हरियाणे के लोगों की क्या हालत है लेकिन अगर आज यह कहा जाय कि वहां पर करप्शन चल रहा है · · · (**व्यवधान**) मैं पंजाब में पैदा हुआ हूं, बंगाली हूं । आप लोगों को सब को जानता हूं । तो मैं कह रहा था कि आज यह करप्शन की बात कर कौन रहा है ? वह कांग्रेसी जिन्होंने 20 साल तक भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ इस देश में नहीं किया । आज अगर यह कहते हैं भ्रष्टाचार के बारे में कि वहां पर आज भ्रष्टाचार हो रहा था, ऐसी सरकार चल रही थी कि जिस सरकार में केवल मंत्री बनाए जा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं कि यहां के प्रधान मंत्री से कि आखिर यह चार और छः मिनिस्टर यहां पर बना दिए गए यह किस वास्ते बनाए गए ? इसीलिए कि आखिर डिफेक्शन न हो । डिफेक्शन न हो, इस वास्ते यह बनाए गए और यह मंत्रि-मंडल को बढ़ाया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं और गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरीके पर कोई फैसला लेने के पहले आखिर सदन में अगर यह चीज आती तो हम लोग यहां अपने विचार रख सकते थे । लेकिन फैसला लेने के बाद तब यहां पर आये हैं कि हमने जो प्रजातंत्र के उसूलों की लाश निकाल दी आप भी अपना कन्धा उसमें लगा दीजिए और अपनी मोहर उस पर लगा दीजिए । हम जानते हैं आज से दो तीन दिन बाद शायद बंगाल में भी वह चुनी हुई हुकूमत जिसने कांग्रेस का जनाजा निकाला, जिसने कांग्रेस के सभापति तथाकथित अतुल्य घोष साहब जो कि बंगाल के शेर कहलाते थे भले ही चाहे वह गीदड़ ही रहे हों, उनको हरा दिया, उसको हटा कर वहां बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन गवर्नर के मातहत लागू करना चाहते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं हरियाणे के लोगों ने भले ही उसे सह लिया लेकिन बंगाल में राष्ट्रपति शासन अगर होगा, अगर वह गवर्नर जो कि आज गृह मंत्री के इशारों पर चलने वाला है, कठपुतली है उनके हाथ की, उसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जायगा तो एक चीज मैं कह दूं कि बंगाल की गलियों में और सड़कों पर उसका मुकाबिला होगा · · · (**व्यवधान**) · · · उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने कोशिश की, काफी कोशिश की कि किसी तरह से वहां की सरकार खत्म हो । लेकिन खत्म नहीं हुई और आज भी कोशिश हो रही है कि जहां पर गैर-कांग्रेसी

हुकूमत हो उसको किसी हालत में खत्म किया जाय। राजस्थान में श्री सुखाड़िया जैसे भ्रष्ट, करप्ट आदमी को जो सोने की चोरी करे, सब कुछ करे उसको बना रखा है इसलिए कि वह खद्दर पहनने वाला है, खादी टोपी पहनने वाला है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज किसी हालत में भी वह किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को रखने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाकई बचाना चाहते हैं तो इसका यह तरीका नहीं है। इस तरीके से राष्ट्रपति का शासन लाद कर सारे देश को वह दावत दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि यहां पर मिलिटरीशाही या अयूबशाही कायम हो।··· (**व्यवधान**) ···ज़ाकिर हुसैन साहब क्या करेंगे उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। करने की ताकत हो तो करें। यहां पर तो ज़ाकिर हुसैन साहब के सिगनेचर्स होते हैं··· (**व्यवधान**) ··· कौन ज्यादा शक्तिशाली है यह बताना जरा मुश्किल है हमारे लिए। मैं तो चाहता हूं कि ज़ाकिर हुसैन साहब के हाथ में खूब ताकत हो, वह और दोनों हाथ से आर्डिनेंस पास करते जायं, गलत आर्डिनेंस और दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन लागू होता चले। अध्यक्ष महोदय, यही कारण था कि हम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस का राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग लड़े थे। सैद्धांतिक उसूल पर लड़े थे हम लोग।

एक माननीय सदस्य : हार गए।

श्री सो०मो० बनर्जी : हां, हार गए। लेकिन गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वह तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : यू० पी० में आपके कम्यूनिस्ट मिनिस्टरों ने इस्तीफा दे दिया या नहीं ?

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह बता दूं कि अभी हमारे भाई साहब जिन्होंने हमें इन्टरप्ट किया है, इस सात महीने में इन्टरप्शन के सिवाय और कोई काम इन्होंने नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० से मैं चुनाव जीता हूं और तीसरी मर्तबा कांग्रेस को हरा कर आया हूं और जब तक जिन्दा हूं कांग्रेस को हरा कर आऊंगा। वह इसलिए कि आज कांग्रेस बदनाम है। आज कांग्रेस की कोई इज्ज़त नहीं है। 1947 से पहले अगर कांग्रेसी कहीं जाते थे तो लोग कहते थे कि देश का सेवक आ गया। लोग अपनी टोपी उतार कर रख देते थे। लेकिन आज क्या हालत है ? सन् 47 के बाद यह देश के शासक हुए और आज देश के शोषक हैं। यह इनका हाल है। इसलिये मैं कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप इस बारे में सोचिये। आप को भी सोचना पड़ेगा क्योंकि आप हिफाज़त करते हैं यहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। अगर इसी तरीके से राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ बंगाल में फिर बिहार में तो फिर जनता को भी हक होगा कि जिस तरीके से चाहे इस सरकार को केन्द्र में जो बैठी हुई है उस को भी हटाए और उसके बाद फिर एक तरफ···मिलिटरी होगी एक तरफ पुलिस होगी और दूसरी तरफ जनता का एका होगा।···· (**व्यवधान**) ····

बार-बार हमारे दोस्त कहते हैं चीन के बारे में, कम्युनिस्ट के बारे में। 50 मील की रफ्तार से 150 मील भागने वालों, ज्यादा बात मत करो। वहां पर भाग के चले आये और हिन्दुस्तान भर में इन्होंने क्या कहा ? जरा आंखों में पानी भर लो। लम्बे-लम्बे भाषण इनके चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, देश की धरती को देने वालों, आज यह बातें मत करो। यह बहादुरी की बात दूसरी किसी जगह जा कर करो। हम लोगों ने देखा है कि कितनी बहादुरी तुम में है।······ (**व्यवधान**) ······चलो मेरे भाई जहां चाहे चल कर चुनाव लड़ लो। चाहे इंडियन स्टाइल से लड़ो चाहे अमेरिकन स्टाइल से लड़ो।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं कहना चाहता हूं, हरियाना में दुबारा चुनाव होगा और चुनाव के बाद कांग्रेस का जनाज़ा फिर दोबारा निकलेगा । और एक दफा जाकिर हुसैन साहब जिन्दा रहे तो दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू कर के देखें क्योंकि केरल में दो दफे कर के हम ने देखा । तो यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान की जनता आज कांग्रेस को चाहती नहीं है और यह कांग्रेस मरी हुई, सड़ी हुई, गली हुई कांग्रेस है । इसको कोई चाहता नहीं है । यह कांग्रेस गांधीजी की कांग्रेस नहीं है । यह अमी चन्द प्यारे लाल की है या बिरला की कांग्रेस है । इस कांग्रेस को हम लोग बिलकुल नहीं चाहते । इन शब्दों के साथ मैं पूरा समर्थन वाजपेयी जी के प्रस्ताव का करता हूं ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (हिसार): माननीय अध्यक्ष जी, आनरेबिल होम मिनिस्टर साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया है, मैं उसकी ताईद के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि इसके सिवाय और कोई कदम नहीं था कि गवर्नर की इस रिपोर्ट के बाद यही कदम उठाया जाना ज़रूरी था । जब से हरियाणा स्टेट बनी है, मेरा वहां की पोलिटिक्स से गहरा ताल्लुक रहा है । मैं कुछ वहां के हालात हाउस के सामने रखना चाहता हूं ताकि यह हाउस समझ सके कि वहां पर असलियत और झगड़ा क्या है ।

सबसे पहली बात तो यह है जोकि खुशी की बात है कि वहां की असेम्बली को तोड़ दिया गया । मेरा शुरू से यह खयाल था, अगर हमारे दिमाग में, अगर हमारे आनरेबिल होम मिनिस्टर के दिमाग में यह सवाल होता कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेन्ट बनानी है तो शायद वह असेम्बली को न तोड़ते, उसको सस्पेण्ड करते । मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि असेम्बली अगर न तोड़ी जाती, तो करप्शन और ब्राइबरी फिर दोबारा शुरू हो जाती और पता नहीं उसका अन्जाम क्या होता । इसलिये उसको तोड़ना ज़रूरी था ।

अब जहां तक हरियाणा की पोलिटिक्स का सवाल है, मैं अपने अपोज़ीशन के भाइयों से अपील करूंगा वह ज़रा समझने की कोशिश करें, मैं शुरू से यह महसूस करता हूं कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिये ईमानदार आदमियों की ज़रूरत होती है । भाइयो, हरियाणा के अन्दर कोई पार्टी का झगड़ा नहीं था, आइडियोलोजी का झगड़ा नहीं था, वहां पर तो पर-सेनेलिटी का झगड़ा था । अगर मैं पिछले वाक्यात आपके सामने रखूं तो आप मेरी इस बात को तसलीम करेंगे—पिछले चुनाव हुए, दो पार्टियां वहां कामयाब हुईं, कांग्रेस पार्टी को 48 सीटें मिलीं और जनसंघ को 13 सीटें मिलीं । और किसी पार्टी ने, जिसने वहां इलेक्शन लड़ा था, कामयाबी हासिल नहीं की । इस के साथ-साथ मैं यह बात भी कहना चाहता हूं, शायद दूसरे भाइयों को न पता हो कि जब हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दिये, तो जनसंघ पार्टी के पास अच्छे उम्मीदवार नहीं थे, जो जनता में पोपुलर हों । उनको हमारे उन उम्मीदवारों को स्वीकार करना पड़ा जिनको हमने ठुकरा दिया था । इससे ज्यादा कांग्रेस की हर दिलअज़ीज़ी का सबूत क्या मिलेगा·····

श्री यज्ञदत शर्मा : गलत है ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : यह बिलकुल सही है, मैं उनके नाम ले सकता हूं ।

श्री यज्ञदत शर्मा : मैं आपके स्टेटमेन्ट को चेलेन्ज करता हूं, बिलकुल गलत है, बुनियादी तौर पर गलत है । इस सवाल पर मैं चाहता हूं कि एन्क्वायरी कमेटी बैठे ।

MR. SPEAKER : No. Please. He has a right to say what he wants to say.

श्री राम कृष्ण गुप्त : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो बात कही है, ज़िम्मेदारियों के साथ कही है । अगर यह बात गलत साबित हो जाये, तो मैं आज ही इस हाउस से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । श्री बनवारी लाल झक्कड़

का नाम सुना होगा, उसने कांग्रेस टिकट के लिये एप्लाई किया । हमने यह तय किया हुआ था कि जो भाई कांग्रेस टिकट के लिये एप्लाई करे, उसको हलफनामा देना पड़ेगा और 250 रु० फीस देनी पड़ेगी, इस के अलावा एक हज़ार रुपये बतौर ज़मानत के इस बात के लिये देने पड़ेंगे कि अगर उसे टिकट नहीं मिले, तो वह इलेक्शन नहीं लड़ेगा । श्री बनवारी लाल झक्कड़ ने टिकट के लिये एप्लाई किया और 1,250 रु० जमा कराये ....

श्री यशदत शर्मा : एक नहीं हर स्टेट में ऐसे आदमी हैं, जिन्होंने कांग्रेस टिकट के लिये एप्लाई किया, लेकिन टिकट न मिलने के बाद फिर भी चुनाव लड़ा ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैंने यह नाम इस लिये यहां पर पेश किया, चूंकि मेरे स्टेटमेन्ट को गलत ठहराया गया था । फिर इन्होंने नारनौल के अन्दर जनसंघ का कैन्डीडेट तलाश करने की कोशिश की, जब कोई नहीं मिला, तो आखिर में उसी बनवारी लाल झक्कड़ को, जिस के 1,250 रु० हमने ज़ब्त कर लिये थे, जनसंघ का टिकट देकर इलेक्शन लड़ाया गया ....

श्री यशदत शर्मा : 1952 से नारनौल में जनसंघ जीतती चली आ रही है । जहां पर ये कह रहे हैं कि कैन्डीडेट नहीं मिलता, वहां 1957 में जीती, 1962 में जीती । आप यह गलत स्टेटमेन्ट दे रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपका जो वक्तव्य चल रहा है, यह आउट आफ प्वाइंट है—आज का विषय हरियाणा का प्रोक्लेमेशन है ।

MR. SPEAKER : Will you kindly sit down ? Is it that everybody have spoken only 100 per cent truth and there has been no exaggeration? What is all this ? Everybody has a right to say, what he has to say. There is bound to be some exaggeration.

श्री राम कृष्ण गुप्त : अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं और भी कई नाम गिना सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं चाहियें, बस, एक नाम दिया है, काफी है ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : मेरे कहने का मतलब यह था कि वहां पार्टी का झगड़ा नहीं था, वहां आइडियोलोजी का झगड़ा नहीं था, वहां परसेनलिटी का झगड़ा है, वहां पर परसनल लाइक्स और डिस्लाइक्स हैं—इसलिये मैंने ये मिसालें दीं । अगर मेरी बात से किसी सज्जन को दुख हुआ हो, तो मुझे इस बात का अफसोस है, लेकिन मेरा किसी भी पार्टी की नुक्ताचीनी करने का मकसद नहीं था ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक वहां के लोगों का सवाल है, वहां के लोग इस कदम से खुश हैं और आपको भी यह समझना चाहिये कि इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था । आप कांस्टीट्यूशन का नाम लेते हैं—ठीक है । मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मकसद यह है कि देश के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर एक खुशहाल स्टेट कायम करें और उस खुशहाल स्टेट को बनाने में सबसे ज्यादा ज़िम्मेदारी लेजिस्लेचर की है । एम० एल० एज़० की है, एम० पीज़० की है—आप मेरी इस बात को तसलीम करेंगे । मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं जो एम० एल० ए० सुबह कांग्रेस में है, शाम को दूसरी पार्टी में है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारे में भी बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन छः-छः दफा एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करें, मैं आपसे पूछता हूं वहां कांस्टीट्यूशन कैसे कामयाब होगा ? वेलफेयर स्टेट कैसे इस्टेब्लिश होगी ? इसके अलावा और भी कई चीजें ऐसी हैं जो रिपोर्ट के अन्दर नहीं आईं—जैसे लालच देकर, रुपया देकर, पैसा देकर, परमिट देकर एम० एल० एज़० को किसी भी तरीके से काबू करने की कोशिश की गई । इसलिये यह ज़रूरी था ।

अब जहां तक रायेआमा का सवाल है, उस के बारे में मैं दो-तीन मिसालें आपके

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

सामने रखना चाहता हूं । कुछ दिन पहले मेरे माननीय दोस्त बलराज मधोक का अखबारों में एक बयान निकला था और उन्होंने यह कहा था कि प्रेजीडेन्शल रूल ही, राष्ट्रपति का शासन ही, हरियाणा के अन्दर वाहिद हल है । आप सब भाइयों ने वह बयान अखबारों में पढ़ा होगा । इसके अलावा चन्द रोज़ हुए हमारे हरियाणा के जनसंघ के प्रधान चौधरी मुख्तयार सिंह मेरे से मिले । उन का बयान भी अखबारों में आया कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, बिलकुल यही बात उन्होंने मुझ से कही और यह भी कहा कि आप को भी इस किस्म का बयान दे देना चाहिये ताकि जल्द से जल्द हरियाणा के अन्दर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाये ।

इसके अलावा कल का हिन्दुस्तान टाइम्स आप देखिये—वहां के चीफ मिनिस्टर राव वीरेन्द्र सिंह ने खुद गवर्नर से इस बात की सिफारिश की है कि हरियाणा के अन्दर मिड-टर्म इलेक्शन होने चाहियें । मैं आप से पूछता हूं कि जब हरियाणा की दो पोलिटिकल पार्टीज़, जोकि असेम्बली में रिप्रेज़ेन्ट करती हैं, इस बात के लिये तैयार हैं और वहां का चीफ मिनिस्टर इस बात की सिफारिश करता है फिर कौनसी बात रह गई, जिसकी कि इसमें कमी है ।

श्री रबी राय (पुरी) : विधान सभा को बुलाइये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार भंग करने की ज़रूरत नहीं थी ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : इसलिये मैं तो यही कहता हूं कि होम मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने जो यह कदम उठाया है, सही कदम उठाया है और इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था ।

मेरे भाई एस० एम० बनर्जी ने यह कहा कि जबरल इलेक्शन के बाद हरियाणा के अन्दर कांग्रेस पार्टी का क्या हशर होगा ?

मैं बातें कम करता हूं लेकिन मैं उनको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि अगर जनरल इलेक्शन हुआ तो 70 फी सदी सीटें हरियाणा कांग्रेस हासिल करेगी । यह बात कहने से साबित नहीं होगी बल्कि आनेवाले हालात आपको साबित करेंगे । उसके कारण हैं । वहां के लोगों का, वहां की जनता का कांग्रेस की आइडियल्योजीज़ के अन्दर विश्वास है जिसका कि सबूत मैंने दे दिया । अच्छे से अच्छा आदमी जो असेम्बली में पहुंचना चाहता है वह यह समझता है कि एक ही रास्ता है असेम्बली में जाने का कि किसी तरीके से मुझे कांग्रेस का टिकट मिल जाये । 50 परसेंट तो मैं उसमें कामयाब हो गया और वह इसलियें क्योंकि वहां की जनता कांग्रेस के साथ है, साथ थी और साथ ही रहेगी । इन चन्द शब्दों के साथ मैं फिर होम मिनिस्टर साहब ने जो रेज़ूलेशन पेश किया है उसकी ताईद करता हूं ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्री चह्वाण साहब यह प्रस्ताव रख कर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे । लगता है कि शायद वह इतिहास के बड़े मशहूर व्यक्ति हो जायेंगे क्योंकि जब से यह लोक सभा चली यह तीसरी राष्ट्रपति की घोषणा हुई, एक मणिपुर की, दूसरी राजस्थान की और यह तीसरी हरियाणा की हुई और शायद अभी हाथ साफ कर रहे हैं और अगर वह हाथ साफ हुआ तो न जाने अभी कितनी और जनतंत्र की हत्याएं आप के हाथों होंगी ।

अभी जब श्री चह्वाण बोल रहे थे तो मैं ताज्जुब कर रहा था कि जल्लाद यह कब से बन गये ? जल्लाद का काम है क़त्ल करना और चह्वाण के हाथों इस देश का जनतंत्र क़त्ल हो रहा है । ऐसा कार्य गृह मंत्री श्री चह्वाण कर रहे हैं ।

श्रीमन्, यह राज्यपाल का जो प्रतिवेदन है और माननीय चह्वाण का जो भाषण है उनमें एक ही चीज़ है और वह है दल-बदल की ।

दल-बदल होने से एक समस्या उत्पन्न हुई । प्रशासन में वह चीज आ गई । इसलिये बहुमत होते हुए भी वहां की सरकार ठीक नहीं चल रही थी । दल-बदल में गृह मंत्री के इस इरादे के साथ मैं इत्तिफाक करता हूं । मैं उनकी तारीफ भी करता अगर यह सही मायनों में दल-बदल से चिंतित होते क्योंकि उधर दल-बदल कारण है हरियाणे के मंत्रिमंडल को खत्म करने का तो दूसरी तरफ बिहार में दल-बदल की कोशिश हो रही है और शोषित संघ के साथ पिछड़े वर्ग के आदमियों को मुख्य मंत्री बनाने की लालच देकर दल-बदल करने का प्रयास कहीं कराया जा रहा है । कहां चिन्ता है दल-बदल की ? अगर वह पिछड़े वर्ग के मंत्री बनाने की चर्चा होती तो मैं समझता । इंदिरा जी में इतनी हिम्मत होती कि वह अपने पद से हट जातीं और उनकी जगह पर कहीं चह्वाण और जगजीवनराम आ जाते । अगर ऐसा होता तो मैं समझता कि बहुत तबीयत साफ है और उनके इरादे नेक हैं लेकिन इनकी बात क्या, एक जगह दल-बदल से सरकार भंग होती है विधान सभा भंग होती है और दूसरी तरफ दल-बदल का बराबर प्रयास जारी है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सभी लोग इस बात पर मुख्यत: विचार करें कि क्या सही मायने में दल-बदल से यह सरकार चिंतित है, क्या यह सदन चिंतित है । यह सही है कि दल-बदल नहीं होना चाहिये । मैं भी ऐसा ही चाहता हूं । लेकिन यह हम कब चाहते थे जो माननीय अशोक मेहता ने दल-बदल किया तब भी हम चाहते थे कि नहीं होना चाहिये । जब माननीया सुचेता ने इस प्रकार बड़े दल-बदल पर चिन्ता प्रकट की, जब गेंदा बाबू का दल-बदल हो गया था और मंत्रिपद उनको दिया जा रहा था तब भी हम को चिन्ता थी और आज भी चिन्ता है लेकिन आज जो सत्तारूढ़ दल है केन्द्र की सरकार है उसको दल-बदल की चिन्ता नहीं है । उसको चिन्ता है कि उसके दल की सरकार कैसे रहे । मैं साफ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के शासन का अर्थ है कांग्रेस की सरकार । इसी लिये और लोगों ने तर्क दिया कि अगर सरकार चाहती कि वहां कांग्रेस की सरकार बने तो विधान सभा नहीं भंग होती ।

आज यह दल-बदल क्या है? यह हरियाणे की सरकार का अस्तित्व ही दल-बदल पर है । दल-बदल ही अगर कारण था तो अब तक यह सरकार क्यों नहीं भंग की गई ? वह इसलिये कि अभी तक बराबर श्री भगवतदयाल और देवीलाल जी वगैरह वह सब मिल कर यह भरसक प्रयत्न और प्रयास कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से बहुमत प्राप्त करके वहां कांग्रेस को सत्तारूढ़ करें लेकिन जब वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुए तो फिर अन्ततोगत्वा यह बर्खास्तगी का कदम आया श्री चह्वाण का और चक्रवर्ती साहब के जरिये वहां उस विधान सभा को भंग कर दिया । इस तरीके से अगर चिन्ता होती तो क्या मैं श्री चह्वाण से पूछ सकता हूं कि राजस्थान में जिस नाटकीय ढंग से वहां की सरकार को खत्म किया गया और बराबर कांग्रेस को मौका दिया गया कि वहां के विधायकों को तोड़ा जाये, पद के जरिये, मंत्रिपद के जरिये और संख्या का जो यहां जिक्र हुआ तो वह जरा पूछें अपने सुखाड़िया साहब के वहां पर मंत्रियों की क्या संख्या है ? क्या अभी जो संख्या है वह मुस्तकिल बनी रहेगी या उसे और बढ़ाने वाले हैं ? यह सब चीजें देखने की हैं । इस तरीके से अगर देखा जाय तो आपके इरादे तो शुरू ही से साफ हैं । राजस्थान के अन्दर नवम्बर में और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में आप के राज्यपाल ने कौन से गुल खिलाये ? उन्होंने जानबूझ कर मौका देकर कांग्रेस को वहां पर सत्तारूढ़ कराया जिसका कि हमने परिणाम देखा । कहां उनके साथ जनता थी या विधायक थे ? वह सरकार आपकी 18 दिन चली और बाद में वह अपदस्थ हो गई । राज्यपाल ने आपके यही काम किया । मध्य प्रदेश में भी क्या राज्यपाल के जरिये यह काम आप करने जा रहे हैं और उसी तरीके से आज बंगाल में क्या होने जा रहा है ? मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे मधोक साहब यहां इस समय बैठे हुए हैं और मैं उनको

[श्री रामसेवक यादव]

चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूं कि भारत सरकार यह जो गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने और समाप्त करने का फांसी का फंदा तैयार कर रही है उससे खबरदार रहियेगा क्योंकि मधोक साहब आपकी गर्दन मोटी है और कभी भी वह फंदा आपकी गर्दन में डाला जा सकता है। आप कहीं इतमीनान से न बैठ जाइयेगा। इसी तरह रंगा साहब को भी मैं कहना चाहूंगा कि वह भी खबरदार रहें, इतमीनान करके न बैठ जायें कि अभी उड़ीसा में जो उनकी स्वतंत्र पार्टी की सरकार है उसका चूंकि वहां पर विशाल बहुमत है इसलिये वह सरकार बनी रहेगी। मैं मधोक साहब को कहूंगा कि वह इस घमंड में न बैठे रहें कि उनका मध्य प्रदेश में काफी बहुमत है और वहां वह बना रहेगा। जब एक बार फांसी का फंदा तैयार कर लिया गया है तो वह एक-एक करके आप जैसे लोगों के गलों में भी किसी न किसी दिन पड़ने वाला है। इसलिये मैं सब लोगों को और उस में मैं उधर के लोगों को भी शामिल करता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जनतंत्र के साथ इस तरह से खिलवाड़ मत करो। कहा भी गया है :

"पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। जरूरत आज इस बात की है कि दूसरों की विचार-धाराओं की कद्र करो। हमारा संविधान फेडरल है इसलिये सूबे में कोई दूसरे दल की सरकार होगी और केन्द्र में उससे भिन्न दल की सरकार होगी तो उसको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार सूबों में गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है लेकिन यह 6 महीने भी मामला नहीं चल पाया। 6 महीने यह मंत्री लोग गद्दी पर नहीं रहे। वह इस 6 महीने में परेशान होते रहे और दरअसल बात यह है कि एक भी व्यक्ति बगैर मंत्री या मुख्य मंत्री के पद के नहीं रहना चाहता है। कहने को मेरे यह कांग्रेसी मित्र जनतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन अमल में उसके अनुसार आचरण नहीं करते। यदि वह 6 महीने भी विरोधी दल की हालत में बैठते, विरोधी दल का क्या कर्त्तव्य है उसको अदा करते तो उन की दुहाई का कुछ अर्थ रहता। वैसे मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई गैर-कांग्रेसी सरकारों से बहुत प्रसन्न नहीं हूं। उनको जो करना चाहिये वह उसे नहीं कर रहे हैं। विरोधी दल की हैसियत से जो रोल कांग्रेस को अदा करना चाहिये था वह जरा अपने सीने पर हाथ रख कर सोचें कि क्या उन्होंने उसे अदा किया है? क्या उन्होंने एक भी जनता के सवाल को लेकर राज्यों में कोई संघर्ष किया है? क्या उन्होंने जनता के हित में कोई भी प्रोग्राम चलाया है? उनको तो बस यही चिन्ता रहती है कि किसी तरीके से हम मंत्री बन जायें और चपड़ासी लोग हमें सलाम करने लग जायें और हमारे चूतड़ के नीचे कुर्सी आ जाये। यह स्थिति है आज चह्वाण साहब और इस रास्ते पर चल कर के आज जनतंत्र को खत्म करके जिस ढंग से आप चल रहे हो जिस ढंग का व्यवहार चुनाव के बाद आप कर रहे हो वह जनता के मन में घाव करता चला जा रहा है। आज केन्द्र की कांग्रेसी सरकार सत्ताधीशों की तरह से और अंग्रेजों की तरह से अपने राज्यपालों का इस्तेमाल करके कांग्रेस विरोधी सरकारों को खत्म कर रही है और यह अगर चीज घर कर गई तो फिर यह केन्द्र से भी बाहर हटने के लिये केन्द्र से अपने को हटाने के लिये एक न्योता दे रही है। अगर कहीं आप ने शक्ति का इस्तेमाल किया तो आज नहीं तो कल वह तंग आयद बजंग आयद वाली कहावत चरितार्थ होने जा रही है। अगर ऐसी घटनाएं देश के जनतंत्र में जम्हूरियत में घटें तो उसकी जिम्मेदारी इस सरकार पर और गृह मंत्री जी पर होगी। इसलिये सजग रहिये, सचेत रहिये। अब भी बाज आ जायें और जनतंत्र में अपने विश्वास का परिचय दें।

मैं अपने श्री चह्वाण को बतलाना चाहता हूं कि आज कश्मीर में इस सिलसिले में क्या

हो रहा है ? कश्मीर में जनतंत्र चल रहा है लेकिन वहां पर क्या हालत हो रही है ? 26 आदमियों के नाम खारिज किये गये जब चुनाव हो रहा था । आज 34 आदमियों के सहारे 75 की अल्पमत की सरकार है क्योंकि मैं बतलाना चाहता हूं कि वहां पर 26 आदमियों के नाम रिजैक्ट किए गए 13 विरोधी हैं । दो जगहें खाली हैं, 41 हुए और 75 में 34 कांग्रेस के हैं । अब कहां बहुमत है । रोज हल्ला मचाते हैं और शिकायतें की जाती हैं लेकिन वह हमारी सरहद की सरकार एकदम नाकामयाब है लेकिन चूंकि वह कांग्रेस की सरकार है इसलिये उसे जैसे भी हो सके कायम रखा जा रहा है । मैं चाहूंगा कि भारत सरकार यह दो चश्मे से देखने की आदत छोड़ दे । अगर आप ने एक चश्मे से देखा होता तो इस देश की जनता आप पर यकीन करती कि इनके इरादे नेक हैं । आज वह इस बात पर विश्वास करती है कि यह सही मायनों में जनतंत्र के दोस्त हैं । यह जम्हूरियत के दुश्मन नहीं हैं और वह सही मायनों में जनता की बहबूदी चाहते हैं और चाहते हैं कि पुर-अमन इस देश की हुकूमत चले और विधान टूटे नहीं लेकिन जब आप दो तरीके के कानून बनायेंगे और आपकी यह चिन्ता बनी रहेगी कि दूसरे दलों से लोग टूट-टूट कर आपकी पार्टी में शामिल हों तो मुश्किल है और तब तो आप फिर विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल को मुख्य मंत्री भी बना देंगे । यह नहीं होना चाहिये कि जब उधर से सदस्य टूट कर इधर आयें, तो कहा जाय कि प्रजातंत्र की हत्या हो गई । इस तरह राजकाज नहीं चला करते हैं, इस तरह नीतियां नहीं चला करती हैं । इस सरकार को किसी नीति के सहारे चलना चाहिये ।

इसलिये मैं गृह मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि वह यह कलंक अपने माथे पर न लें । इस प्रकार की दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं । यह तीसरी दुर्घटना है । हमें डर है कि इस प्रकार की दुर्घटनायें और भी होंगी और उस कलंक के भागी गृह मंत्री होंगे । मुझे उनके साथ हमदर्दी है । लेकिन मैं उनको कहूंगा कि वह यह कुकर्म न करें । मैं चाहूंगा कि जिस तरह से बंगाल के राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि किस का बहुमत है, किस का अल्पमत है, यह बात विधान सभा में तय हो, हरियाणा में भी उसी नीति का अनुसरण किया जाय । हमें बहुमत सम्बन्धी निर्णय का अधिकार गवर्नर की स्वेच्छा पर छोड़ कर गवर्नरों को 1935 के एक्ट के अधिकार नहीं देने चाहियें और इस प्रकार इस देश में 1935 के एक्ट की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिये, बल्कि जम्हूरियत और जनतंत्र की जड़ें मजबूत करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

इसलिये गृह मंत्री इस प्रस्ताव को वापस ले लें और राज्यपाल को कहें कि वह हरियाणा के मुख्य मंत्री के द्वारा विधान सभा को बुलायें । अगर राव वीरेन्द्र सिंह का बहुमत होता है, तो उनको चलने दें; अगर उनका अल्पमत होता है, तो फिर जिसका बहुमत होता है, उसको शासन चलाने दें । अगर उसके बाद भी गृह मंत्री इस नतीजे पर पहुंचें कि हरियाणा की सरकार कानून और संविधान के अनुसार नहीं चल सकती है, तो फिर उसको भंग कर दिया जाय । यह सरकार और गृह मंत्री इस तरह से काम करें कि वह देखने और समझने में जनतांत्रिक लगे, न कि जनतंत्र की हत्या करने वाला । इसलिये जनतंत्र, मानवता ईमानदारी और संविधान के नाम पर गृह मंत्री इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal) : I have stood up today to defend the action of the President in promulgating President's rule in Haryana. I entirely agree with the Opposition when they say that democracy should be saved. Democracy cannot be saved in the manner that the Opposition preaches here. Democracy has been butchered and murdered and raped in Haryana. It is the duty of the Governor and the President to save democracy. It is with that end in view that this step has been taken to uphold the

[Shri P. Venkatasubbaih]

constitution and to save democracy from disrepute and ridicule.

The Governor in his letter to the President has clearly stated the events that have taken place in the course of the few months since the present Ministry in Haryana had taken office. Several Members have changed their party affiliations. Members have been speaking hereabout defections. Defections to gain political power and defections because of ideological changes have been very well listed here. My hon. friend Shri Ranga is not here at the moment. When he defected, he defected to found a new political party but not for political gain. He was here as a Member of Parliament when he defected from the Congress. He started to go to the KMPP, and then to the KLP and then from the NLP he came back to the Congress, and from the Congress he again defected and started the Swatantra Party. That is not defection at all, but that is only an ideological conviction. When it suites the Opposition Members to say that this is the sort of defection that has taken place, we have nothing to say against our great leader Shri Ranga.

I should mention one other instance also. Shri Asoka Mehta when he joined the Congress Party was never a member of a legislature. He joined the Congress purely on an ideological basis. So, I would remind my hon. friends who speak here about defections that they must also have this aspect in view.

श्री रवि राय : इसके बाद वह योजना कमीशन के उपाध्यक्ष बना दिये गये ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Haryana has a hoary past. It was there that the battle of Kurukshetra was fought, the battle of *dharma* against *adharma* was fought. Here, for the first time, another battle of democracy is being fought now.

In that context, I want to congratulate the Home Minister that he is responsible to uphold the democratic functioning here.

When Shri Bal Raj Madhok, Shri Vajpayee and other members speak, I find that there is a split personality. Shri Madhok issued a statement deploring the state of affairs obtaining in Haryana, but Shri Vajpayee says here....

SHRI BAL RAJ MADHOK : I did issue a statement deploring the situation in Haryana, in Bengal and in Jammu and Kashmir. You pick up Haryana and leave out Bengal and Kashmir, that is my grouse.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : I am coming to that.

Shri Ram Sevak Yadav very nicely chides the Jana Sangh members not to fall in the trap of the Congress, because he is afraid of his own party members in the States where the SSP and the Jana Sangh and other parties are the partners, we can hear the rumblings in the parties.

श्री मधु लिमये : आप लोग तो एक पार्टी होते हुए भी झगड़ते हैं ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : They have learnt to hate the Congress, but they have not learnt to like each other, the constituent parties of their Governments. That is the difficulty. Shri Gurnam Singh, the Punjab Chief Minister, says that he is disgusted. Shri Charan Singh, the U.P. Chief Minister says that he cannot carry on. Whom are they blaming? They blame themselves for the sorry state of affairs they have brought in the various Governments.

One factor that I would like to impress upon this House is that the Ministry has been dismissed and the Assembly has also been dissolved. If really the Congress Government at the Centre had the idea of reviving the Congress Party which is in a minority and indulging in horse-trading they would certainly have kept the Assembly alive. The fact that the Assembly has been dissolved and the Ministry dismissed clearly proves that the Central Government is as much anxious as the opposition members to save democracy. Many political manoeuvres could have been made by dismissing the Ministry and encouraging the Congress Party there to draw defectors from the other groups, because defection is taking place, as the Governor has pointed out as the changing of a coat.

Shri Vajpayee has been saying that the Governor has issued a statement that still Rao Birendra Singh commands a majority,

and he is not going to dismiss his ministry, also that he has agreed that he would wait till the result of the pending by election is known, but he has not read the later portion where this view has been taken by the Governor that a succession of events took place which go to show that there is no stability, that the morality of the legislators has gone down, and the administration has come to a standstill. The officers do not find security, everybody is in constant fear, the Government has come to a standstill. In such circumstances, what else could have been done by any other Government than to dismiss this unwanted ministry which is going against democracy?

Coming to the other points raised by hon. Members, I would only say that the Congress Party is as much interested as the members of the opposition to uphold the Constitution and preserve democracy. We are not lagging behind in upholding the constitutional provisions, but when the events go to show that the people have lost confidence in the administration there, when there is no semblance of an orderly or stable Government, what else could any Government have done? The very same opposition would have accused the Central Government if they had not taken this step of saving democracy in Haryana.

Another factor I wanted to bring to the notice of this House is that, as my hon. friend Shri Ram Kishan Gupta has pointed out, the leaders of the Opposition should fight the battle of the ballot. They should go to the people and prove that the action of the Central Government is contrary to the principles of democracy. It is not as if President's rule is going to be perpetuated for years together. It is only for the preservation of democracy that this step has been taken. The extreme step of dismissing the Ministry has been taken only under certain compelling circumstances.

With these few words, I defend the action taken by the Central Government.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai) : Mr. Speaker, Sir, I was a little bit amused when I saw the moral pose taken by the Home Minister as well as my friend Mr. Venktasubbaiah and Mr. Gupta, on this question. What is it that the President's rule has been imposed in Haryana for? The Governor does not say that the constitutional provisions have broken down anywhere in that report. I am not going into the question whether the Governor is entitled to ask for the dissolution of the Assembly when the constitutional provisions have not broken down. Everyone knows that this is the constitutional provision. Therefore, I am not going into that question today.

The Governor of the State of Haryana arrogates to himself the right to order the political life of that particular State. And what is that political life in that State? The State Congress party—I am reading from the report—

> "....led by Pt. Bhagwat Dayal Sharma could not forget or forgive Rao Birender Singh for having started the game of defection from the party. Efforts were made almost continuously to topple the Ministry in co-operation with Shri Devi Lal who wanted to form a Ministry under his leadership."

Mr. Venkatasubbaiah was talking of a split personality in reference to some Members in the Opposition. I want to know this : the Minister sitting there, everyone of them, has got a split personality : one personality as members of the Working Committee and leaders of the party and another personality as members of the Cabinet here. What is it that has happened? Either the Haryana Congress party is a part or a unit of the All-India Congress party or it is not. If it is a unit of the All-India Congress party, the people sitting there, the Ministers sitting there, also have got their own say. In that case, the easiest thing for them would have been to discipline them, the unit of the Haryana Congress party and tell them, "Look here, you cannot play this game and ask people to defect from this side or that side." That is the simple thing that they could have done. Why is it that they did not do that? There are many people here who talked about morality. It is amusing for me to hear of morality when they talk of morality. They have been talking of defections.

There was a time in this country, in 1937 or 1938, I remember, when in the then Central Provinces, the Congress Chief Minister Dr. N. B. Khare, despite the Congress Working Committee's directive, conspired with the Governor. And what did

[Shri P. Ramamurti]

the Congress party do? The Congress party immediately disowned him and took disciplinary action against him and expelled him from the Congress party. Not a single dog barked in this country when Dr. N. B. Khare was hounded out of public life. That was the position in 1937. Those were the days when the Congress party, the All-India Congress National Congress, was engaged in the struggle against British imperialism. There was something to inspire the people of this country. That party today, after Independence,—what is the position of that party which had led the struggle for Independence and which had won the support of the entire people of this country? What is the state of the country today? If political life in Haryana, if political life in Travancore-Cochin, if political life in Orissa, if political life in other parts of the country has come to this pass, I say the main responsibility is that of the Congress party and of no other party.

You had the biggest opportunity to see that political life in this country was conducted in a clean way. But from the very beginning, you started the defections. Mr. Venkatasubbaiah talked about Mr. Ranga's defection and justified it on political and ideological grounds. But what did the Congress Party do in 1952 in Madras when it was reduced to a minority? He must have heard the names of Ramaswami Padayachi and Manickavelu Naicker. Political corruption was started by you and nobody else in this country. What was the aim? The aim was, somehow or other, the Congress party must be in power and nobody else. Mr. Venkatasubbaiah just now said, "After all, we are not saying that the Congress party is going to come to power in Haryana." When I heard that eloquence, I was reminded of the Sanskrit saying *Vriddha Nari Pativrata.* After all, you are unable to get the Congress Party in power there. What can you do? There is no way out. What is the use of trying to be moral about it?

The Home Minister was saying, the Governor has not spared the ruling party. Is that all? Here was the Governor who after 31st October wanted to give an opportunity to call the Assembly. Between that and now, why did he change his mind? The defections were there earlier also. What has happened during the last 20 days for him to change his mind? I dare say, this report was made to order. These split personalities, sitting here, as members of the Congress Working Committee had something else in their mind. As members of the Central Cabinet, they decided, "We have got to attack some other ministry. It is better that this ministry is attacked first, so that we may not be charged that we are doing something with regard to West Bengal." Therefore, they must have decided like that two days back or yesterday and suddenly the very same Governor, who took a different opinion only 20 days ago, comes forward as the purifier of the political life of Haryana. With people like Biju Patnaik and others, can you purify the political life of this country? During the last 20 years, in State after State, Congress rule stands as the biggest monument of corruption in this country. I cannot understand how political life is going to be purified by this. If you are really interested in purifying the political life, what are you doing in West Bengal? You are asking them to form a ministry saying "We shall support you". It is by these inducements of supporting a ministry that you want to topple the present ministry there.

My party never asked anybody to join it saying "We will make you minister". My party has always said, "Come and join our party. We promise you in return, not office, but jail, bullets and sufferings for the common people of this country." (*Interruptions*). Therefore, I can talk about political morality, because our hands are absolutely clean. Supposing for a moment the position was otherwise; supposing the Congress party has been in power and it had not lost its majority, but people were defecting from this side to that side. Would this Home Minister have come forward with a presidential proclamation and a Governor's report of this type? Absolutely not.

Absolutely not. It would never have happened. The reality, therefore, is that ever since the Congress Party came to power in 1947, after independence, from that time onwards, the political life. the public life in this country has become corrupt and corroded primarily because this party in power has lost the ideals for which the Indian people fought for their freedom.

All these years people were taken to the Congress Party with inducements of office. Somebody was talking about permits and all that. What else was the Congress Party doing in all these States excepting distributing permits and other things? This has been the bane of it.

Therefore, I would like to point out, finally, that this entire report is not a report which is based upon the constitutional provisions but it is based upon a political assessment of the particular situation in Haryana, and it is no part of the functions of the Governor to go into the political life of Haryana. If tomorrow after the President's proclamation an election takes place, are we sure that the Congress Party is going to put up such people who will not change place? After all, it is their people who changed places. You had a majority of 48. In a few days they changed seats. How are you sure that in Haryana after the elections once again the people who would be elected are going to be very stable and politically loyal to the particular party on the ticket of which they got elected? You cannot promise that. Your policies are such that you cannot promise that. So long as the Congress Party is following certain policies and because as a result of those very policies this kind of political defections have started in a very big scale in this country, I say you will not be able to promise a stable Government. Your talking of morals is nothing more than a ruse by means of which the Congress Party wants to have its own way. It was stated that the Congress Party leader there could not forget and forgive Rao Birendra Singh. Are we to believe that these people who are in the Central Government are made of a different stuff from the members in the Haryana Congress? They are men of the same stuff, of the same breed I would say. Therefore, they also cannot reconcile themselves to the fact that in State after State the Congress Party has been defeated.

Therefore, I oppose this resolution and support the motion moved by Shri Vajpayee for the simple reason that it is a political measure, it is a measure of vendetta for a political purpose and not done in good faith and honesty.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Mr. Speaker, Sir, I have been patiently listening to those who are in favour of the President's Rule in Haryana and those who are opposed to it. It is a fact that I am no admirer of what the Congress has been doing all these years. I know how the Ministry was formed in Madras after elections of 1952 I know many other things. It is said that the Congress should have established such conventions that today they find themselves in a bad role.

I would also submit to the oppositio that they, who criticise the Congress, ough not to take a leaf from the book of the Congress. If they condemn the Congress, I could understand it. But while condemning Congress, if they indulge in those very things that they condemn in the Congress, then I say, they are out of court. One does not take one's morality from one's neighbour whom one considers to be wrong. Though all these coalition governments were formed with great expectations, as one of my friends of the SSP has stated, they have not been able to put their house in order and they have not been able to show the stability that was expected of them. They have ideological quarrels, quarrels of their own ambition, quarrels of their own making. They are falling, not because, I am sure, the Congress is stronger than before, but they are falling by their own weight, by the divisions in their own ranks. Even the Congress fell because of divisions in its own ranks, not because of many evil things that it has done, but because they were not united among themselves. So, if these people are taking a leaf out of the book of the Congress, by going the same way, they seem to be very apt followers of the Congress. I would wish that both parties, whether Congress or the Opposition, would put their hands on their hearts and find out if they have not been instrumental in killing and violating the conventions that ought to rule in a democracy.

When a woman was found to have committed a wrong and people were going to stone her, Christ appeared on the scene and said: let the first stone be hurled by a person who has not sinned with women. Then it is said in the Bible that the crowd melted away. But, I am sure, if Christ appears today and says those words, everybody would try to be the first to hurl a stone to show that he has not sinned with women. The trouble today is that we condemn others for what we do ourselves.

[Shri J. B. Kriplani]

I think the whole nation has to put its head together and find out a solution. It is no use saying that there were defections elsewhere. In life we do not divide things logically. It is no argument for a man who eats meat to tell his vegetarian friend that vegetables also have life. It is no use telling a man why he is marrying within such limits or not. On account of circumstances, we do not act by logical divisions but practica divisions.

Here in Haryana defection has been more often and quicker than anywhere else. One can understand a defection or two. One can even understand a bunch of 25 members leaving an organisation and joining another organisation; but people joining one organisation in the morning, repudiating that organisation in the evening and joining the same or another organisation the next morning cannot be excused. When such things happen and there is a proposal to introduce President's rule, one cannot say that the Central Government has some vicious objective. It may be that certain things are bearable for a certain time but after some time they become unbearable. I have no doubt that in Haryana that limit of crossing the floor has passed.

SOME HON. MEMBERS : Hear, hear.

SHRI J. B. KRIPALANI : I do not want to say these things just to hear "hear, hear" from the Congress Benches. In the past they have done things of which they ought to be ashamed. I am only saying what is fair and just. Let each party put its hand on its heart and say that it has done nothing which injures the nation. Remember the British Empire. By whom was it made? By rogues, rascals, the scums of the gutters in London, the sea thieves, the sea dogs. These people made the whole British Empire.

They were impeached even in Parliament. There is no concealing the fact that it was done by the ruffs that lived in England but the ruffs in England knew that they could make money for themselves but not at the expense of the nation. Here even honest, good people injure the nation for their personal ends. This is the trouble. An empire can be made by rogues and rascals of the kind of Clive and others; here we cannot save our country thoug we are the most moral people and we stand in the world for peace and unity while we are not united among ourselves.

17·00 hrs.

I would appeal to all my friends, whether they belong to the Congress or to the Opposition, to see that they, in their conduct, do nothing that would injure the nation in any way or that would bring about degradation of the democratic rule that we have established. It may be that the Communist Party is honest above others and it has no skeleton in its cupboard. It may be so because they sing the songs to Mao. So there is nothing that they can conceal. They act always honestly. If they are with Mao, they tell you that they are with Mao. The only party that can claim to be very honest and very straightforward may be the Left Communists; but all other parties have to search their hearts. I would not ask Mao's party to search its heart, because it has no heart. Its heart is sold to China. What can I say to them? But to other parties I would humbly submit that they search their hearts and that they do nothing that injures democracy in this country or that injures the interests of this country.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : मान्यवर, देश के इस सर्वोच्च मंच पर शायद कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होगा जो कि राष्ट्रपति के इस प्रॉक्लेमेशन के बहुत पक्ष में होगा या उसे बहुत ही दिल से स्वीकार करता होगा क्योंकि यहां पर जितने भी हम सदस्य लोग हैं, हम सभी लोग उस में सम्मिलित हैं, हम सबों ने लोकतंत्र में अपनी आस्था व विश्वास रखने की शपथ ली है । इस देश का राज-काज जनतंत्री और लोकतंत्रात्मक तरीके से चलाने में अपनी आस्था स्थापित की है परन्तु हम को सोचना पड़ेगा कि आज वह ऐसा कौन मर्ज है, आज वह कौन ऐसी तकलीफ है जिसके कारण आज की केन्द्रीय सरकार को, हमारे राष्ट्रपति को एक ऐसे हथियार का प्रयोग करना पड़ रहा है जिसकी कि आज आवश्यकता पड़ गई है । अगर शरीर के किसी भी भाग में कोई रोग होता है तो

उस रोग को दूर करने के लिये हर तरीके का उपाय किया जाता है परन्तु अगर कैंसर की तरह वह चीज बहुत फैल जाती है और साधारण तरीके से वह चीज दूर नहीं हो सकती तो एक ऐसा भी कदम लेना पड़ता है जैसे कि आज केन्द्रीय सरकार को जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि आज विवशता से लाचारी से कोई स्वेच्छा से नहीं, कोई बहुत खुशी के साथ नहीं, बड़े दुःख के साथ में आज सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। अगर लोकतंत्र को अपने राष्ट्र में, अपने देश में जीवित रहना है तो उस के लिये कोई ऐसा उपयोग इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए काम में लाना पड़ेगा। सरकार के पास आज ऐसा कोई उपयोग नहीं है जिसके माध्यम से लोकतंत्र को जिसको हमारे चाहे उधर के लोग हों चाहे हम लोग हों सब लोग मान्यता देते हैं और उस लोकतंत्र को हम को जीवित रखना है तो मेरे से पहले जो बहुत-से हमारे महानुभाव बोले उन से मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे राममूर्ति जी ने कहा, वह हमारे बहुत ही अध्ययन किये हुए आदमी हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूं, ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई है उन्होंने कहा कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन फेल नहीं करा, तो मैं तो केवल एक गालिब की एक छोटी-सी चीज आप के सामने दो लाइन की रखना चाहती हूं :

"इब्न मरियम हुआ करे कोई।
मेरे दर्द की दवा करे कोई।"

आज हरियाणा में क्या हालत हो रही है ? जनता वहां कराह रही है। एडमिनिस्ट्रेशन पैरेलाइज्ड हो गया है और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। हर तरह के दुःख की आवाजें वहां पर फैल रही हैं फिर भी हमारे भाई कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पैरेलाइज्ड नहीं हो गया है। आज हम को यह नहीं सोचना है कि कांग्रेस सरकार बनेगी या किस की सरकार बनेगी। सोचना यह है कि कोई भी सरकार हो अगर वह अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकती है तो उस सरकार को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी अपने वाजपेयी जी से जिनकी कि मैं बहुत इज्जत करती हूं कि वह हम को बतलायें कि देश में ही नहीं विश्व के अन्य देशों में भी क्या कोई ऐसा उदाहरण पेश है जहां कि अपनी सरकार बनाने का पूरा मौका था फिर भी उस को ठुकरा कर जनता की आवाज को सुनते हुए और अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा में यह कदम उठाया हालांकि वहां पर कांग्रेसी सरकार के आने के आसार थे फिर भी उस ने उस आसार की उपेक्षा करते हुए और पद-लोलुपता से दूर रह कर अपने मन में विष का घूंट पीकर महज जनतंत्र को जीवित रखने के लिये सरकार ने वहां पर आज यह कदम उठाया।

श्री वाजपेयी और अन्य सब महानुभावों की भावना को मैं स्वीकार करती हूं मैं जानती हूं कि उन के दिल में भी एक खलिश होगी एक दर्द होगा। उन के दिल में जनता के प्रति एक अच्छी मूर्ति रखने की इच्छा होगी और वह हम सब के मन में भी है। मैं उन से कहूंगी कि यह एक ऐतिहासिक दिवस है जो हम सबों के बीच में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आया है और मैं अपने उन सब भाइयों से निवेदन करूंगी कि वह भूल जायें कि वह किस पक्ष में हैं और हम किस पक्ष में हैं। आज यह फ्लोर क्रासिंग एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। आज हम को भूल जाना होगा कि किधर का आदमी किधर जाता है। जनता जनार्दन ने हम को चुन कर यहां भेजा है। हम ने जनता को विश्वास दिलाया था कि हम जनता की सहमति लेकर और अपने कांस्टीट्यूशन की शपथ लेकर आज हम यहां बैठ कर किसी भी समय हमारा कोई सदस्य सोचता है कि आज उन विश्वासों से उन को आस्था हट गई है उस का पहला कर्त्तव्य है कि एक ईमानदार व्यक्ति के अनुसार अपने

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

मन में विश्वास रखते हुए और उस शपथ को, जिस लोकतंत्र की शपथ ली है उस संविधान में आस्था रखते हुए सर्वप्रथम वह अपना त्यागपत्र दे और त्यागपत्र देकर जनता के पास पहुंचे और कहे कि मुझे अपनी राय बदलनी है ऐसे सदस्य की मैं बहुत इज्जत करूंगी । मैं चाहूंगी हमारे उधर के भाई यह भूल जायें कि उन के उधर से यहां कितने लोग आये और उसी तरह से हमें भी भूल जाना होगा कि इधर के कितने लोग टूट कर उधर जाते हैं । हमारी स्पीकर्स कान्फ्रेन्स में भी यह चीज आ चुकी है और व्हिप्स कान्फ्रेन्स में भी वह चीज आ चुकी है और उन में हम लोगों ने भी अपनी तरफ से और विरोधी दल के भाइयों ने भी अपनी तरफ से राय जाहिर की है । मैं सबों से निवेदन करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक मौके पर हमें अपने दिल पर हाथ रख कर अपनी अच्छी भावनाओं से यह सोचना है कि यदि हम चाहते हैं कि जनता में लोकतंत्र की आस्था रहे जनता हम लोगों का मखौल न करे जैसा कि गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है :

"They have made a mockery of the Constitution and have brought democracy to ridicule."

जाहिर है कि अगर हम डेमोक्रेटिक हैं और इस देश में प्रजातंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो उन सब चीजों को जो कांस्टीट्यूशन को एक मौकरी बना रही हैं उन को हटाना है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मर्ज काफी बढ़ गया है और समय रहते हमें उस का उपचार करना होगा । इस मर्ज की गम्भीरता आप इसी से समझ सकते हैं कि गरवर्नर महोदय ने अपनी रिपोर्ट में इस ओर इशारा किया है जब वह कहते हैं :

"I had hoped that the people would be tired of these defections and the epidemic of defection would cease and some stability reached. But it seems that in the present conditions of Haryana politics, defection has become endemic."

इसी से मालूम हो सकता है कि वह चीज कहां तक चली गई है और इस मर्ज का मुकाबला करने के लिये यह जो अंतिम हथियार का सहारा हम ने लिया उस के अलावा और कोई मार्ग हमारे सामने रह नहीं गया था ।

मैं पूछना चाहती हूं कि जब 40 की ताकत थी और उन 40 में से 22 विरोधी दल के आदमी ऐसे थे जो किसी न किसी प्रकार से आफिस होल्डर्स थे तो उस में हमारे वाजपेयी साहब ने बहुत सद्बुद्धि दिखाई थी एक बहुत अच्छी परम्परा स्थापित की थी कि उन आफिस होल्डर्स में उन्होंने अपने को नहीं गिना और वह उस पद से दूर रहे थे । मैं इस चीज के लिये उन को बधाई दूंगी और मैं उन से आशा करूंगी कि जिस चीज को शुरू-शुरू में उन्होंने समझा था कि यह सरकार इस के काबिल नहीं है जो सरकार हरियाणा में चल रही है वह इस काबिल नहीं है कि उसे वाजपेयी जी का जनसंघ दल अपना सहयोग दे सके वही चीज आज जाकर हमारी केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार की है । हो सकता है कि इस में कुछ देर हो गई हो । मुझे पूरी आशा है कि वाजपेयी जी और उन के दल से इस कार्य के लिये और एक सच्चे कार्य के लिये जिससे जनता में एक अच्छी चीज आयेगी उस में उन का पूरा सहयोग मिलेगा ।

मुझे कहना है कि गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है :

"....it is being kept preoccupied all the time with the problem of its very survival. Administration is paralysed.... Everyone seems to want to be a Minister or a Parliamentary Secretary. It is bad enough that political support is being sought by offering Ministerial offices at the cost of the tax-payer...."

क्या कोई भी भाई चाहे इधर का हो या उधर का हो क्या इस चीज से इन्कार कर सकता है जो कि गवर्नर ने कही है और क्या

वह अपने को जस्टिफाई कर सकता है मैं यही प्रश्न उन से पूछना चाहूंगी ।

गवर्नर ने अपने पत्र में कहा है :

"....there are good reasons to believe that the defections are being secured by not too honourable means."

जब गवर्नर महोदय यह कहते हैं कि डिफेक्शन्ज को "नाट टू आनरेबल मीन्ज" से प्राप्त किया जा रहा है तो इस टर्म का स्पष्ट अर्थ है कि डिस-आनरेबल गवर्नमेंट चल रही है, एक अस्थिर सरकार चल रही है, जो अपनी जनता के कष्टों और अभाव-अभियोगों को दूर करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर शरीर के उस दूषित अंग को शरीर से अलग करने के लिये सर्जरी या शल्य-क्रिया के अलावा कोई रास्ता नहीं है ।

गवर्नर की रिपोर्ट में कहा गया है :

"Now that so many members of the Legislature have tasted power...."

आप 'टैस्ट पावर' शब्द का प्रयोग देखिये । हम अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नर महोदय ने कितने दुःख और कितनी शर्म के साथ यह बात कही होगी :

"Now that so many members of the Legislature have tasted power and have seen that by threatening to defect...."

'थ्रेटन' शब्द लोकतन्त्र के खिलाफ है । लोकतंत्र और 'थ्रेट' साथ-साथ नहीं चल सकते हैं । लेकिन गवर्नर महोदय अपनी रिपोर्ट में 'टैस्ट पावर' और 'थ्रेटन' दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ।

"Now that so many members of the Legislature have tasted power and have seen that by threatening to defect they can get what they want, it seems to me that no alternative stable Ministry can be formed so long as there are such large numbers of members whose loyalties are so flexible. If the Assembly is convened and either the ruling Party or the opposition can establish its majority, even then there will be no peace or stability in the present circumstances."

मुझे केवल यही कहना है कि अगर यह आशा होती कि कुछ दिनों के बाद वहां की स्थिति स्थिर हो जायेगी, तब मैं कहती कि सरकार ने यह प्रोक्लेमेशन जारी कर के एक गलत कार्य किया है । लेकिन गवर्नर ने अपनी डिस्क्रीशन का उपयोग कर के अपनी राय दी है, स्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन कर के वह इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि ऐसे आसार नहीं हैं कि भविष्य में भी वहां पर एक अच्छी और स्थिर सरकार कायम हो सकेगी । इस स्थिति में मैं मंत्री महोदय के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं—बड़े दुख के साथ, क्योंकि यह प्रोक्लेमेशन हमारे लिये कोई खुशी की बात नहीं है । हमें उसे भी विष की तरह पीना है और उससे अमृत का सृजन कर के हरियाणा में एक अच्छी सरकार स्थापित करनी है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं ।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : If this Government had any love and respect for the Constitution, the law of this country, or for democratic processes, then this Governor's Report would have been thrown into the waste-paper basket. By acting on the advice of the Governor as contained in his Report and by taking recourse to Article 356 for Presidential Rule in the State, they are only establishing a very dangerous precedent. Probably they are not affected by this because, as it appears, there is a deep-laid game; it is a conspiracy; it has been done deliberately to upset non-Congress Governments. A beginning has been made at Haryana which, I must admit, is the weakest link in the whole chain of non-Congress Governments; there is no doubt about that. But they have thought, as a bargain, to strike here.

After all, if the President's Rule is to be promulgated in any State, what are the requirements under Article 356? It is very clear. Either there should be a Constitutional breakdown or there is no chance, whatsoever, of an alternative Ministry being formed. In this document, there is no

[Shri Surendranath Dwivedy]

instance, not even a single instance to show that there has been a breakdown of law and order in Haryana nor in this House has the problem ever been raised by anybody to show that a situation has developed in Haryana where no longer orderly administration can be carried on. (*Interruptions*) The Report does not show that. I want my hon. friend to point out at least a single instance. In a sentence, the Governor says that the administration is paralysed. When does he discover that? He discovers that when it suited him. He did not discover it when so many Ministers were appointed. He says Ministers are appointed to retain the majority of the Government, and this, he terms an abuse of the constitutional powers. Would I take it, Sir, that any expansion of the Ministry or appointment of Ministers is an abuse of the constitutional power? Any Government, Congress or non-Congress, would be accused of that, if that would be the sole criterion to decide what the abuse of power is. There is no question whatsoever of that.

It must also be remembered that the number of Ministers appointed in Haryana will be more than what has been done after the present Governor took charge. Many Ministers have been appointed before that. He has never thought so. When this question was posed to him, rather categorically he says 'No, there has been no occasion. He still commands the majority'. Also, Sir, in this report he does not says that the present Government has lost its majority, lest the President might think that because some Devilal or somebody has gone over to the Congress, the strength of the Congress Party has increased and, therefore, he has lost his majority. Even in his last letter, the Governor has maintained that the present Chief Minister commanded the majority. It is very clearly said. So, I think this has been done for a political purpose, nothing else behind it. The whole excuse that they point out is—we are butchering democracy in order to save democracy.

Sir, so much has been said about defections. I can understand that, I cannot support it and I am not happy about this. We have been condemning these defections. I may recount, Sir, if you permit me, one incident. It was this Party, the Praja Socialist Party; when we left Congress in 1948—those of us who were elected on Congress ticket to the legislature. We resigned our membership from the Assemblies and said that we have no right to continue as representatives, having been nominated by that Party which we have now left. If these people really serious about defections, if they really wanted to establish moral standards, a code of conduct in our political life would have been accepted. A standard would have been established. But what have they done all these years? If defections have come today and pose a problem before them, if anybody is responsible for it, if anybody has corrupted the political life of this country and made democracy a farce, a mockery, it is the Congress Party alone and nobody else. It is very clear from the past history and even today—you are no longer in the Congress Party—but I want to point out so that everybody may know what is happening in this country. Here, everybody realises that after the General Elections these defections are going to become a real danger to the democratic life of this country. And who are encouraging this? When you were in the Congress probably you were President, or not, I do not know, but now the Central Parliament Board passes a resolution rescinding the previous one and invites everybody, whichever Party he may belong to, if he leaves that Party and comes to them, they will simply embrace him. The lead has been given from here....

SHRI NATH PAI (Rajapur) : This is the original sin.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : This is to encourage defections all over the country. Therefore, they have no moral right. Is this action being taken because of defections? Are they worried on account of that? It is not so. If that was so, the whole thing would have ended long long. Who is going to really stop this? Is it the Governor? By taking this action again, it is proved and as has been accused on the floor of this House, that they are really utilising the Governors and working them as political agents to suit the political purposes of the Congress Party in power, nothing else, because the Governor cannot go into the extraneous reasons. The Governor, a salaried servant, is he to dismiss an

elected representative without giving him a chance to test his strength in the Assembly? He himself says that the Chief Minister has a majority. He says himself that on the 20th of December the Assembly was to be convened. 20th December is the date given here in this summary. If that be so, after the receipt of this report, why should Government not have waited till 20th December? The argument is advanced that there might be more defections.

I think it would really be a bad day for this country if we are to believe in these documents. The Governor has stated why he has taken this step. He says:

> "This new State has had a raw deal so far. What Haryana badly needs now is a clean and efficient administration."

And who will bring about this clean and efficient administration? He says:

> "Fresh elections may be arranged as soon as possible after the administration has been toned up by a brief spell of Presidential rule."

We are asked to invoke President's rule in Haryana to tone up administration. Whether our Constitution provides for such a thing or not the Central administration here could be toned up by having a President's rule for a brief spell. Then, the Governor suggests how a stable government could be formed. He has no business to consider whether a stable government is there or not. He has only to consider whether an alternative government could be formed or not. But he has gone into the question of the stability of the government. Who is he to decide that? Who is he, a salaried servant, to decide what constitutes a stable government or what factors cause the stability of a government? Then, he says:

> "It is to be hoped that in mid-term elections so many opportunist legislators would not be re-elected."

How is the Governor going to prevent it? He himself says who is responsible for this state of affairs. He has not spared the Congress Party also because the Congress Party has its own contribution to this sordid game. He says:

> "The defections have become very frequent. The Opposition could never reconcile...."

The term 'Opposition' here refers to the Congress Party. He says:

> "The Opposition could never reconcile itself to its position as a responsible Opposition."

AN HON. MEMBER : It is an irresponsible Opposition.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : He further says:

> "It must bear some responsibility for not having given the Government any peace or chance to settle down to constructive work."

This was exactly what they did in Kerala where some other Government was in power. The same process has been started here. the hint goes from the Centre to the effect; Create trouble; create uncertainty; create situations in which it will be possible for us to invoke this article', and the Governor is a very handy weapon in their hands for playing this game.

SHRI NATH PAI : Therefore, they do not want to have any consultations in regard to the appointment of Governors.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Some hon. friends have said that it is a murder of democracy. I would say that it is the end of democracy in this country.

MR. SPEAKER : After murder, naturally it is the end. Where is the need to say that again?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : They say that it is the murder of democracy in Haryana. But I say that it is the beginning of the end of democracy in this country.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : After murder, there is *post-mortem* also.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : I am afraid that this kind of thing may happen not only in Haryana but in other States also. Of course, I must make it very clear that I have no sympathy with the Haryana Government. I do not approve of whatever has happened even if my party happens to be a partner in any government. I do not approve of the opportunistic policies that are being followed by non-Congress as well as Congreess Governments to take

[Shri Surendranath Dwivedy]

back the defectors in order to have a majority and to make them Ministers overnight. That is a very shameful act. It is a disgrace, such a thing continues in our political life. Therefore, I have no sympathy and no love at all if Haryana Government goes; if many other State Governments of that type also fall, I will not be sorry for them, but it must be based on some constitutional procedure. There must be valid reasons why President's rule should be invoked.

Therefore, I would appeal to the House once again. Of course, the Opposition will vote against the Home Minister's resolution. But I would like to tell my Congress friends that still there is time and they may give an opportunity again by not approving this Proclamation, and let the Haryana Assembly meet and let the strength of the Government be tested, and if it falls, then let them order fresh elections and whoever commands a majority may form the government by following the ordinary or normal democratic procedure.

With these words, I oppose the Home Minister's resolution and support Shri A. B. Vajpayee's motion.

MR. SPEAKER : There are three more Parties which are yet to be given a chance, and there are one or two unattached Members also. I have got three or four names more in the Congress Party's list also. I know that several of them are getting up every time. But I would say that if the speeches are brief, I could give them a chance. Let them take five minutes each and speak without repetition. Of course, some other names also have come in later on. But at least I have got three or four names in the Congreess Party's list.

Therefore, may I request members to be brief, so that four from this side and four from that side can speak ?

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : आधा घंटा टाईम बढ़ा दिया जाय ।

MR. SPEAKER : We must have the audience. If you guarantee me the audience, I will extend the time.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri) : Mr. Speaker Sir, I think even the opposition parties will have to admit that this report of the Governor is equally condemnatory of the Congress Party and the other coalition parties that exist in Haryana. I am glad that a condition exists in our country where a Governor appointed by the Central Government gives in his report this kind of censure, shall I say, against the Congress Party.

What is it that we are discussing at present ? I think basically it is not so much a question of defections, because defections have occurred in other democratic countries without shaking the foundations of the Government. We are discussing basically a law and order situation, we are discussing basically whether it is possible under the present circumstances for the administration to continue, and the Governor has said in this report at page 7 :

> "There will be no peace and stability in the present circumstances."

He has also stressed again that what is basically necessary for Haryana is a clean and efficient adminstration.

It is possible that after six months, when elections take place, the same sort of situation may arise. I do not rule it out, but what has become quite evident in today's debate is that we have been busy, both sides, throwing mud at each other. We have forgotton the geographical position of Haryana, we have forgotten what repercussions it will have both on our defence position and on our border situation if there is political instability in that area.

What is the prime function of the Government ? The prime function of the Central Government is to see that the security of the country is ensured. I ask you : is it too much to suspend the Assembly for six months in order to give that peace and security in that area ?

It hurts the Congress party as much as it hurts you. If this report of the Governor were not an honest statement of facts, if as you have said, it has been engineered by the Central Government, why should he say in this report what he has done about the Congreess Party? It could

have been smoothed over; it could have been presented as a nice cake with icing on it. No, he has given the true situation, even you have to admit it.

SHRI PILOO MODI (Godhra) : She says even you have to admit it.

MR. SPEAKER : I do not have to admit anything.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : I would ask; would this be possible if the communist party were in power ? I wonder. Would it be possible to have this kind of an honest report ? That is the main thing.

Now, Sir, the debate here has gone on the constitutional basis and on the basis of defections, but basically I think it is a political aspect. After all, they are as much anxious to get political power as we are, and there are as many people in their party who are averse to political power as there are in our party. All of us are not dying to become Ministers and all of you are not dying to get rid of Ministerships either. We are all sons and daughters of the same soil. Whatever you have said, we have also said. So much noise about the political situation that exists in Haryana has been made. But I think the Union Government has done nothing more but to ensure that the people of Haryana have political security which is so essential to the country at this stage.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr. Speaker, Sir, I am fully opposed to the resolution moved by the Home Minister.

AN HON. MEMBER : Matter of duty.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : It is not a matter of duty; it is a matter of understanding and it is a matter of politics and common sense. It is not a mere matter of duty. Sir, it has been said that what has happened in Haryana is a mockery of democracy. But what is happening here today is a mockery of the Constitution. Let us understand what we are doing. The Governor has been praised for giving a good report, and an impartial report. I say it is a halting report. I do believe his mind is not there. That is why he has said at several places, he has given many sentences which support the contentions to be raised by the Opposition. At three places, he says that the Government has a majority. In the end also he says it commands a majority, but says "All the same, I do not want this; I want President's rule".

What has the President done ? I do not think the President has gone into the various statements made by the Governor. The proclamation has followed the language of the Constitution : it simply says :

> "....received a report from the Governor of the State of Haryana and after considering the report and other information received by me...."

The "other information" has not been vouchsafed to us, to this House. The proclamation refers to these two items, just as in the Constitution. Nowadays, in the criminal courts, when charges are made, the language of the Penal Code or the Criminal Procedure Code is just cited whether the offence actually is covered by it or not. Similarly, the President's proclamation says : "....Other information received by me....." Will the Minister be pleased to lay on the Table of the House the "other information received" by him ? What is it that the Governor says ? Although he says that there is majority for the present Government he says that still he does not believe that there will be a stable government.

Now, a few days ago, he was quite satisfied with the statement of the Chief Minister that the strength could be tried in the Assembly on 3rd December. Suddenly, he changed his mind. Why? Because some other defections or crossings over took place. Well, then, did he invite the Chief Minister again and say : "A few days ago, my dear friend, I agreed with you that you can try your strength on the 3rd December, but today the situation is changing. What is your position ? No, I think he was having conversation with somebody else in Delhi rather than with the Chief Minister in that place.

Is it true that no one is satisfied with defections and personally nobody wants

[Shri Tenneti Viswanatham]

these defections and we are also equally unhappy over these defections. But what are we to do ? In a changing society, in a developing society, as it is called, with changing values, we are now on the threshold of a new kind of life here, and therefore certain things happen.

All the same, the Constitution is above all those things. Has the Constitution failed ? Is the Government unable to run the administration according to the provisions of the Constitution ? That is the question. But the Governor has simply said that the administration is paralysed. How many times did we not have the administration paralysed on account of quarrels in the ruling groups ? From time to time, from State to State, we have these reports. Even at the centre it happens. The report of Mr. Gorwala also referred to such things Yet, nobody thought of superseding these governments and imposing President's rule.

This is a very bad precedent. Why did the Government think of it at this stage ? This is ill-timed and it shows undue haste. Apparently there is somethig else in the mind of Government beside Haryana. They have got 7 or 8 non-Congress Governments and they are getting very uncomfortable about them. They wanted to start somewhere, but this is a very bad precedent. Let us stick to the Constitution. If the Haryana Government should go, if it deserves to go, let it go. Nobody will weep over that. But why not wait till 3rd December ? The Governor says, he is tired, If we have got a TB patient, naturally everyone in the house is tired. But we do not kill the patient. This Government has undertaken the duty of cremating a person even before he dies. This is very wrong. Democracy might have been made a mockery in Haryana. But let us not all combine here and make a mockery of the Constitution. I have absolutely no personal axe to grind anywhere, but I am anxious about some constitutional conventions. One convention at least which this Government should learn is to have some patience. Why are you so impatient. When the Governor was at first satisfied that it was a reasonable request to wait till 3rd December, why should Delhi be so impatient ? That is my question and let us ponder over it.

17·38 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor) : Sir, the one point on which the whole question hinges is the constitutionality of the President's action in issuing the proclamation. It has been admitted on all hands that Haryana politics stinks now. Actually I had borrowed that term from a leader of the opposition this morning. The politics of Haryana stinks so much that it is an act of kindness and advancement of India's democracy. It helps us; it gives some fresh air in the suffocating atmosphere. I do not want to go into all the allegations they have made or all the consequences and nightmares trotted out by some communist friends about west Bengal and so on.

One point that needs to go down our hearts is that no government can fail to respond to the basic democratic forces. In Haryana what happened after the general elections is known. There might be some defections from the Congress party. There was an alternative government. But when the response of the Government to the legislature becomes doubtful and when the response of the legislature to the electorate becomes nil, it functions in mid-air and as a true democrat, I would not hesitate to say that the surgeon's scalprum has to be used. It is essential that somebody on behalf of this democracy and our Constitution —I am very proud to say that my party.. (*Interruptions*).

I am not defending only myself. I would also defend Shri Asoka Mehta. We in 1953 laid down that Indian democracy requires to be guided under certain compulsions. It is those compulsions— excuse me for saying that—of a backward economy that forces us in a direction of polarisation with the Congress. That polarisation today is the only hope of India's democracy.

I know that the different forces that are working in India have given us that

type of combination governments that are threatening to explode every moment, and that is no signal to India's democratic survival. It is necessary that this point goes down home and every one of us realises that.

The constitutional functioning has to be put in a proper way. We must function in a constitutional way. The Congress Party might have committed certain mistakes. It does not matter. But when comes to deciding the trend of India's democracy we have to cry a halt at some point. There is no doubt that the Central Government which is entrusted by the Constitution with a duty, has to discharge that duty. The President and the Governors have a duty under the Constitution to see that the constitution functions in a proper manner and to report on the failure of the constitutional machinery in any State. That has to be done. The constitutional machinery fails when ministerial responsibility fails. Instead of a minister feeling that he has lost the confidence of the electorate and of the legislature and resigning, when he tries to make more ministers as a way out that is the point at which the constitutional machinery has failed (*Interruption*).

I am sorry to say that it has not been realised that the entire legislture has been dismissed including the Congress members. It is not that only the non-Congress members have been dismissed. The entire legislature has been dismissed and this is the most constitutional appeal to the people. When we appeal to the people, let this House support this appeal. Let all of us jointly tell the people. As Shri Vajpayee said, let us make a convention right now, let us lay down rules and norms right today, let us lay down patterns of behaviour for legislators and tell the electorate in Haryana to see that people who have behaved in a most irresponsible manner should no longer qualify to represent them.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : जनाववाला, मैं यहां आनरेबुल होम मिनिस्टर साहब के इस मोशन की ताईद करता अगर उन्होंने एक ही तरीके से इस किस्म के बाकयात के साथ फैसला किया होता या एक ही स्टिक से हर एक चीज को मापा होता । हरियाणे में जो कुछ हुआ गवर्नर की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति के एलान के मुताबिक हुआ । हरियाणे में अब तक मेजारिटी है मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर के साथ और राष्ट्रपति के पास गवर्नर की रिपोर्ट के अलावा और भी इनफारमेशन है जिसकी कि बिना पर वह यह ऐक्शन ले रहे हैं । साथ ही वह यह कहते हैं कि डेमोक्रेसी का तकाजा है राय आम्मा का तकाजा है कि ऐसी गवर्नमेंट को पावर में न रहने दिया जाय जिसके साथ लोगों की ताईद न हो ।

अब काश्मीर को लीजिए । 75 मैम्बर हैं वहां असेम्बली के । उन 75 में से 26 आए हैं रूलिंग पार्टी के । मैं नहीं कहता हूं कांग्रेस पार्टी उस को । यहां कुछ गलतफहमियां होती हैं कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट वहां पर है । किस पार्टी की है किस पार्टी की नहीं है यह मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं रूलिंग पार्टी की कहता हूं कि 26 वाई रिजैक्शन हैं 13 हैं अपोजीशन के । हो गये 39 । 2 सीटें खाली हैं हो गये 41 । जो रूलिंग पार्टी है वह 34 को स्ट्रैथ से वहां एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है गवर्नमैंट चला रही है । इसके सिलसिले में राष्ट्रपति के पास वफ्द गये । तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने युनैनीमस्ली रेजोलूशंस पास किये कि उन के साथ राय आम्मा नहीं है । राय आम्मा उन के बरखिलाफ़ हैं लेकिन वह वहां पर बैठे हुए हैं । हमें कहा गया कि पेटीशन करो और पेटीशन से फैसला होगा । एलैक्शन कमिशन के रिमार्क्स को अगर देखा जाय तो काश्मीर का एलैक्शन बजाय खुद कोई एलैक्शन नहीं है यह खुद चीफ़ एलैक्शन कमिश्नर ने नोट किया है । उस के बाद कायदे कानून के मुताबिक आज तक 9 महीने हो गये फैसला वहां होना चाहिए

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

था लेकिन वहां अभी तक एक पेटीशन के अलावा, हालत यह है कि आउट औफ़ 60 पेटीशंस, 3 पेंडिंग हैं हाईकोर्ट में, उन की तरफ मैं रैफ़र नहीं करता लेकिन 56 पेटीशंस जो इस जमात के खिलाफ़ हैं 41 का रिजैक्शन हो गया है जिन में से 26 वाई आउटराइट रिजैक्शन हैं और 1 का रिजैक्शन औन एकाऊंट औफ़ इजैक्शन है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है । हालांकि एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया था लेकिन 11 सितम्बर को एक ही दिन में कानून पास करके ट्रिब्यूनल को भी खत्म कर दिया गया । 11 सितम्बर से इस वक्त तक वह मामला लटका हुआ है । जिस स्पीड से पेटीशन का फैसला होना चाहिय वैसा नहीं हुआ है । एक पैटीशन का कायदे कानून के मुताबिक 6 महीने के अन्दर फैसला हो जाना चाहिए लेकिन 9 महीने के अन्दर एक पेटीशन हुई तो उस के हिसाब से तमाम पेटीशंस के लिए कम से कम 30 साल चाहिएं । मतलब इस का यह हुआ कि 30 साल तक वही लोग रहने दिये जायं जिनके कि पास जनता की कोई सपोर्ट नहीं और यह साबित कर के दे देंगे और साबित किया जबकि वह उसमें गये । मैं उन एलैक्शंस की मैरिट्स और डिमैरिट्स में नहीं जाता । वहां भी हर तरफ से हर पार्टी की तरफ से डिमांड हुई । मैं इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि उनके जरिय सब जगह एक रौड इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और अगर वैसा किया होता तो मैं यकीनन हरियाणे में उन के ऐक्शन की ताईद करता और जोरशोर से ताईद करता । लेकिन जैसा मैंने कहा मरकजी सरकार एक ही रौड सब जगह इस्तेमाल नहीं कर रही है । यह बदकिस्मती की ही तो बात है कि जहां दरअसल माइनारिटी है और आप भी मानते हैं कि वहां पर माइनारिटी है लेकिन वहां पर वह माइनारिटी गवर्नमेंट बैठी हुई है और टस से मस नहीं हो रही है । अब जब यह हकीकत है कि हमारी उस स्टेट में माइनारिटी गवर्नमेंट बैठी हुई है और आप भी मानते हैं कि वहां पर माइनारिटी की गवर्नमेंट कायम है तो फिर इंसाफ का तकाजा है कि उसे बर्खास्त किया जाय और हमारे साथ इंसाफ किया जाय । लेकिन हमारे साथ इंसाफ भी क्या होता है ? पेटीशंस जिसके लिए वाजे क़ायदे क़ानून बनाय हुए हैं उनकी तरफ भी कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है । मैं उन से यह दरख्वास्त करूंगा कि यह सही है कि आप एक कदम उठा रहे हैं मुल्क में सही मायनों में डमोक्रसी के फंक्शनिंग के लिए और मैं चाहूंगा कि इस डिफैक्शंन की रोज व रोज बढ़ती जा रही बीमारी को खत्म करने के लिए आप तमाम पार्टियों को साथ लेकर पार्लियामेंट के जरिए एक कानून लागू करें कि आयन्दा डिफैक्शंस नहीं होंगे ताकि इस किस्म के दल बदल कि शाम को आज किसी पार्टी में हैं सुबह को निकल कर दूसरी में चले गये और शाम को उस से भी हट कर तीसरी में चले गये यह जो डिफैक्शंस हो रहे हैं कि शाम को है सुबह को नहीं यह बीमारी खत्म हो जाय ।

मेरी शिकायत इस सरकार से यह है कि जब ऐक्शन लेने का वक्त होता है तब तो हम खामोश बैठे रहते हैं लेकिन जब ऐक्शन लेने का वक्त नहीं होता है । तो ऐक्शन ले लिया जाता है और नेचुरली इसके खिलाफ रिजैंटमैंट होना लाजिमी है । मैं उन से यही अर्ज करूंगा कि आनरेबुल होम मिनिस्टर खुद वहां पर गये और इस हाउस के भी काफ़ी मैम्बर वहां पर गये थे, मैं आज उन सब के यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने वहां के उलटे सीधे हालात देख कर वायदा किया था कि वह वहां की हालत को ठीक करने के लिए दबाव डालेंगे लेकिन अभी तक वही ढेंगी रफ्तार वहां पर चल रही है । ला एंड आर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर नदारद है, एकोनामी तबाह है, सिक्योरिटी है नहीं, करप्शन बढ़ा हुआ है और इन सब चीजों के रहते हुए भी

आप उस गवर्नमेंट को इन पावर में रख रहे हैं।

मजबूरी क्या है और क्या नहीं है, मैं नहीं जानता। वे लोग अपने आप को कांग्रेस गवर्नमेंट कहें, शौक से कहें, लेकिन हम उन को नहीं मानते हैं। वह एक रूलिंग पार्टी है। वह क्या है और क्या नहीं है, यह दुनियां जानती है।

हरियाणा के गवर्नर को जो रिपोर्ट एवान के सामने रखी गई है, उसके मुताबिक 78 मेम्बरान में से 40 मेम्बरान तो चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वहां के चीफ मिनिस्टर को रीमूव किया जा रहा है। इसके मुकाबले में जम्मू-काश्मीर में एक मुख्तलिफ रौड बरता जा रहा है। अगर सब केसिज में एक ही रौड इस्तेमाल किया जाय, तो शायद किसी को क्रिटिसिज्म और नुक्ताचीनी करने का मौका नही मिलेगा। सैंटर को यह देखना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ गवर्नमेंट ऐसा हो, गवर्नमेंट ऐसे फंक्शन करे, जिस से लोगों का भला हो। मैजूलिंग रौड एक होनी चाहिए—अपने लिए एक और दूसरों के लिए दूसरी, यह मुनासिब नहीं है।

[شری غلام محمد بخشی : جناب والا - میں یہاں آنریبل ہوم منسٹر صاحب کے اس موشن کی تائید کرتا اگر انہوں نے ایک ہی طریقے سے اس قسم کے واقیات کے ساتھ فیصلہ کیا ہوتا یا ایک ہی اسٹک سے ہر ایک چیز کو ماپا ہوتا - ہریانے میں جو کچھ ہوا گورنر کی رپورٹ کے مطابق راشٹرپتی کے علان کے مطابق ہوا - ہریانے میں اب تک میجارٹی ہے موجودہ چیف منسٹر کے ساتھ اور راشٹرپتی کے پاس گورنر کی رپورٹ کے علاوہ اور بھی انفارمیشن ہے جس کی بنا پر وہ یہ ایکشن لے رہے ہیں - ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں - کہ ڈیمو کریسی کا تقاضا ہے رائے عامہ کا تقاضہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ کو پاور میں نہ رہنے دیا جائے جس کے ساتھ لوگوں کی تائید نہ ہو -

اب کشمیر کو لیجئے - ۷۵ میمبر ہیں وہاں ایسمبلی کے - ان ۷۵ میں سے ۲۶ آئے ہیں رولنگ پارٹی کے - میں نہیں کہتا ہوں کانگریس پارٹی اس کو - یہاں کچھ غلطفہمیاں ہوئی ہیں کہ کانگریس پارٹی کی گورنمنٹ وہاں پر ہے - کس پارٹی کی ہے کس پارٹی کی نہیں ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں رولنگ پارٹی کی کہتا ہوں کہ ۲۶ بائی ریجکشن ہیں ۱۳ ہیں اپوزیشن کے - ہو گئے ۳۹—۲ سیٹیں خالی ہیں ہو گئے ۱۴ - جو رولنگ پارٹی ہے وہ ۳۴ کی اسٹرینتھ سے وہاں ایڈمنسٹریشن چلا رہی ہے گورنمنٹ چلا رہی ہے اس کے سلسلے میں راشٹرپتی کے پاس وفد گئے - تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یونینیمسلی ریزولوشنس پاس کئے کہ ان کے ساتھ رائے عامہ نہیں ہے - رائے عامہ ان کے بر خلاف ہے لیکن وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں - ہمیں کہا گیا کہ پٹیشن کرو اور پٹیشن سے

پاس جنتا کی کوئی سپورٹ نہیں اور یہ ثابت کرکے دے دیں گے اور ثابت کیا جب کہ وہ اس میں گئے — میں ان الیکشن کی میرٹس اور ڈیمیرٹس میں نہیں جاتا وہاں بھی ہر طرف سے ہر پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ ہوئی— میں اس موقعہ پر پرائم منسٹر سے اور ہوم منسٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ورده سب جگہ ایک روڈ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور اگر ویسا کیا ہوتا تو تو میں یقیناً ہریانے میں ان کے الیکشن کی تائید کرتا اور زور شور سے تائید کرتا— لیکن جیسا میں نے کہا مرکزی سرکار ایک ہی روڈ سب جگہ استعمال نہیں کر رہی ہے یہ بدقسمتی کی ہی تو بات ہے کہ جہاں دراصل مائنارٹی ہے اور آپ مانتے ہیں کہ وہاں پر منارٹی ہے لیکن وہاں پر مائنارٹی گورنمینٹ بیٹھی ہوئی ہے اور ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے— اب جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری اس اسٹیٹ میں مائینارٹی گورنمینٹ بیٹھی ہوئی ہے اور آپ بھی مانتے ہیں کہ وہاں پر مائنارٹی کی گورنمنٹ قائم ہے تو پھر انصاف کا تقاضہ ہے کہ اسے برخست کیا جائے— اور ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے— لیکن ہمارے ساتھ انصاف بھی کیا ہوتا ہے— پٹیشنس جس کے لئے واضح قاعدے قانون بنائے ہوئے ہیں ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی

[شری غلام محمد بخشی]

فیصلہ ہوگا - الیکشن کے ریمارکس کو اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا الیکشن بجائے خود کوئی الیکشن نہیں ہے یہ خود چیف الیکشن کمشنر نے نوٹ دیا ہے — اس کے بعد قاعدے قانون کے مطابق آج تک ۹ مہینے ہو گئے فیصلہ وہاں ہونا چاہئے تھا لیکن وہاں ابھی تک ایک پیٹیشن کے علاوہ حالت یہ ہے کہ آوٹ آف ۶۰ پیٹیشن ۳ پینڈنگ ہیں— ہائی کورٹ میں ان کی طرف مین ریفر نہیں کرتا لیکن ۵۶ پیٹیشن جو اس جماعت کے خلاف ہیں ۴۱ کا ریجکشن ہو گیا ہے جن میں سے ۲۶ بائی آوٹ رائیٹ ریجیکشن ہیں اور ۱ کا ریجیکشن اون اکاونٹ آف ابجیکشن ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے— حالانکہ ایک ٹریبونل مقرر کیا گیا تھا لیکن ۱۱ ستمبر کو ایک ہی دن قانون پاس کرکے ٹریبونل کو بھی ختم کر دیا گیا ۱۱ ستمبر سے اس وقت تک وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے — جس سپیڈ سے پیٹیشن کا فیصلہ ہونا چاہئے ویسا نہیں ہوا ہے— ایک پیٹیشن کا قاعدے قانون کے مطابق ۶ مہینے کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہئے لیکن ۹ مہینے کے اندر ایک پیٹیشن ہوئی جو اس کے حساب سے تمام پیٹیشن کے لئے کم از کم ۳۰ سال چاہئیں— مطلب اس کا یہ ہوا کہ ۳۰ سال تک وہی لوگ رہنے دئے جائیں جن کے

چل رہی ہے— لا اینڈ آرڈر اور ایڈ منسٹریشن وہاں پر ندارد ہے ایکونامی تباہ ہے سیکورٹی ہے نہیں کرپشن بڑھا ہوا ہے اور ان سب چیزوں کے رہتے ہوئے بھی آپ اس گورنمنٹ کو ان پاور میں رکھ رہے ہیں—

مجبوری کیا ہے اور کیا نہیں ہے— میں نہیں جانتا— وہ لوگ اپنے آپ کو کانگریس گورنمینٹ کہیں— شوق سے کہیں لیکن ہم انکو نہیں مانتے ہیں— وہ ایک رولنگ پارٹی ہے— وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے— یہ دنیا جانتی ہے—

ہریانہ کے گورنر کی جو رپورٹ ایوان کے سامنے رکھی گئی ہے— اس کے مطابق ۷۸ ممبران میں سے ۳۰ میمبران تو چیف منسٹر کو سپورٹ کرنے کے لئے موجود ہیں— لیکن پھر بھی وہاں کے چیف منسٹر کو ریمو کیا جا رہا ہے— اس کے مقابلے میں جموں کشمیر میں— ایک مختلف راڈ برتا جا رہا ہے اور سب کیسز میں ایک ہی راڈ استعمال کیا جائے— تو شائد کسی کو کریٹیسزم اور نکتہ چینی کرنے کا موقع نہیں ملیگا— سینٹر کو یہ دیکھنا چاہئے کہ ایڈمنسٹریشن آف گورنمینٹ ایسا ہو— گورنمینٹ ایسے فنکشن کرے— جس سے لوگوں کا بھلا ہو— میزرنگ راڈ ایک ہونی چاہئے— اپنے لئے ایک اور ہے— میں ان سے یہ درخواست کرونگا کہ یہ صحی ہے کہ آپ ایک قدم اٹھا رہے ہیں بلکہ میں صیح معنوں میں ڈیموکریسی کے فنکشنگ کے لئے اور میں چاہوں گا کہ اس ڈیفکشن کی روز بروز بھڑتی جا رہی بیماری کو ختم کرنے کے لئے آپ تمام پارٹیوں کو ساتھہ لیکر پارلیامینٹ کے ذریعے ایک قانون لاگو کریں کہ آئیندہ ڈیفیکشن نہیں ہوں گے تاکہ اس قسم کے دل بدل کہ شام کو آج کس پارٹی میں ہیں صبح کو نکل کر دوسری میں چلے گئے اور شام کو اس سے بھی ہٹ کر پھر تیسری میں چلے گئے یہ جو ڈیفیکشن ہو رہے ہیں کہ شام کو ہمیں صبح کو نہیں یہ بیماری ختم ہو جائے میری شکائیت اس سرکار سے یہ ہے کہ جب ایکشن لینے کا وقت ہوتا ہے تب تو ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں لیکن جب ایکشن لینے کا وقت نہیں ہوتا ہے تو ایکشن لے لیا جاتا ہے اور مجبوری اس کے خلاف ریزنٹمینٹ ہونا لازمی ہے— میں ان سے یہی عرض کرونگا کہ آنریبل ہوم منسٹر خود وہاں پر گئے اور اس ہاوس کے بھی کافی ممبر وہاں پر گئے تھے میں آج ان سب کے یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے وہاں کے الٹے سیدھے حالات دیکھ کر وائدہ کیا تھا کہ وہ وہاں کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لئے دباؤ ڈالینگے لیکن ابھی تک وہی بے ڈھنگی رفتار وہاں پر

[شری غلام محمد بخشی

دوسروں کے لئے دوسری— یہ مناسب نہیں ہے—]

श्री दलबीर सिंह (सिरसा) : डिपुटी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर हरियाणा में प्रैजिडेंट्स रूल लागू करने का फ़ैसला किया गया । मैं इस फ़ैसले का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । गवर्नर ने अपनी रिपोर्ट में सब वाकयात लिखे हैं । मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह रिपोर्ट सब माननीय सदस्यों के पास है । लेकिन इन वाकयात को देख कर कोई भी आदमी यह महसूस करता है कि वाकई हरियाणा में प्रैजिडेंट्स रूल लागू किया जाना चाहिए ।

वहां पर जो हालात पैदा किये गये, जो अफ़रा-तफ़री हुई, जिस तरह से मेम्बरों का कभी इस तरफ और कभी उस तरफ फ्लोर-क्रासिंग हुआ, सियासी सतह पर जो नाटक खेला गया, जिस तरह से वहां खरीदो-फ़रोख्त हुई, जिस तरह से वहां वजारतें आफ़र की गईं, जिस तरह से मेम्बरों को अपनी तरफ खींचने के लिए लोभ लालच और दूसरे नामुनासिब तरीके इस्तेमाल किये गए, इन सब बातों से हरियाणा की हुकूमत में पतन हुआ और उस पतन का यह असर हुआ कि जनता यह महसूस करने लगी कि यह सरकार जितनी जल्दी खत्म हो जाय, उतना ही अच्छा है । वहां का हर शहरी यह महसूस करने लगा, मेम्बरान एसेम्बली ने यह महसूस किया, गवर्नमेंट के छोटे मुलाजिम से लेकर बड़े से बड़े अफसर ने यह महसूस किया कि यह सरकार बिलकुल पैरालाइज्ड है । जब इन सारे हालात और वाकयात की रिपोर्ट गवर्नर ने प्रैजिडेंट को भेजी, तब वहां पर प्रैजिडेंट्स रूल लागू किया गया । इस के बावजूद आपोजीशन की तरफ से यह एतराज किया जाता है कि ऐसा क्यों किया गया । आज आपोजीशन डिफरेंट स्टैंडर्डज का नाम लेकर, दो चार गालियां, देकर, सरकार को करप्ट कह कर, तरह तरह के इल्जाम लगा कर कांग्रेस को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहती है और अपने आप को जस्टिफाई करना चाहती है ।

चूंकि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और वहां के आम लोगों और वहां की सरकार से मेरा सम्पर्क है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी छोटा या बड़ा सरकारी मुलाजिम मुझे मिला और सरकार के बारे में हमारा परामर्श हुआ, तो उन सबने यह ख्याल जाहिर किया कि यह कोई सरकार नहीं है । हर हुकूमत का कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई प्रोसीड्यर होता है । यह तो कोई तरीका नहीं है कि जो आर्डर सेक्रेटेरियट लेबल से शुरू होता है, वह डायरेक्ट छोटे मुलाजिम को भेज दिया जाय और अगर छोटा मुलाजिम कहे कि यह प्रोसीड्यर के मुताबिक नहीं है, यह आर्डर सेक्रेटेरिएट से आना चाहिए था, तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाये, उस का नाजायज हैरासमेंट किया जाये, उस को कई तरह से तंग किया जाये, उसका ससपेंशन किया जाये ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में क्या नहीं हुआ । मैं सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब भी पार्लियामेंट के मेम्बरान से इस बारे में विचार-विमर्श होता था, तो वे यह महसूस करते थे कि हरियाणा में आखिर यह क्या हो रहा है कि कोई मेम्बर आज इधर जा रहा है और अगले दिन उधर जा रहा है । सब माननीय सदस्य यह महसूस करते थे, लेकिन आज इस ऐवान में आकर वे महज पोलीटिकल स्पीचिज देकर कह रहे हैं कि सरकार और प्रैजिडेंट का यह ऐक्शन जस्टिफाइड नहीं है ।

मैं इस बात को नहीं मानता। हम सब में खुले तौर पर और ईमानदारी से सही फैसले को सही कहने की स्पिरिट होनी चाहिए।

आपोजीशन ने हर बात का इल्जाम और हर बात की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाली है, लेकिन उन्होंने कोई स्टैंडर्ड तो रखा होता। जैनेरल इलैक्शन के बाद कुछ स्टेट्स में कांग्रेस का और कुछ में गैर-कांग्रेसी सरकारें कायम हुईं और देश के लोगों को इन दोनों में मुकाबला करने का मौका मिला। लोगों ने देखा कि गैर-कांग्रेसी सरकारें किस तरह चलती है। आज प्रैजिडेंट के फैसले को डैमोक्रेसी का पतन और डैमोक्रेसी की हत्या कहा जाता है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कई स्टेटस में एक किस्म का चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा हुआ कई पार्टियों न मिलकर अपने उसूल और अपनी आइडियालोजीज को पूर करके सरकारें बनाई। वे सरकारें कितने दिन चलीं? उन से जनता की क्या फायदा हुआ? आज सारी तस्वीर लोगों के सामने है। मुझे हरियाणा जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर दोबारा इलेक्शन का मौका आ जाए, तो वह बता दे कि वह पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है।

जिन पार्टियों और लोगों ने मिल कर ये सरकारें बनाईं, उन को इन थोड़े ही दिनों में नशा हो गया और वे कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते। बेदार एक गरीब लेकिन अच्छा शाइर है। उसने कहा है, "एक ही घूंट में बेदार बहक उठा है, ऐसे कमजरफ़ को महफिल से उठा दे साकी।" इन लोगों को थोड़े ही दिनों में कारों की सैर, झंडों के फहराने, रेस्ट-हाउस में ठहरने और सलामियां लेने से हुकूमत का नशा हो गया और ये अपनी कुर्सियों को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़े ही दिनों में "बहुत बेआबरू हो कर तेरे कूचे से हम निकले।"

श्री रघुबीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हरियाणा में जो कुछ होता रहा और आज यहां जो कुछ सुना और देखा, उस के आधार पर मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आज की जो घटना है, यह पाप का घड़ा फूट रहा है। यह अलग बात है कि इस पाप के घड़े को इसलिए फोड़ा जा रहा है कि पाप का दूसरा घड़ा भरने में कुछ दिन और बीत जायेंगे।

हरियाणा में राजनीतिक व्यक्तियों का भ्रष्टाचार, चाहे वे किसी भी दल के हों, इस दर्जे तक पहुंच गया था कि हरियाणा के लोगों को अपने आप को राजनीतिज्ञ कहने में शर्म आने लगी थी। हरियाणा के राजनीतिक व्यक्ति उस भगोड़ी औरत की तरह हो गए थे, जिस को एक वक्त का खाना खिला कर कोई भी अपने घर में रख सकता है।

मैं कह सकता हूं कि ऐसी औरत के भरोसे कोई भला आदमी अपने घर को नहीं रखेगा। इसके साथ ही साथ यह ठीक है कि आज यह कहा जा रहा है कि जनतंत्र की हत्या हुई है। मैं यह कहता हूं कि जनतंत्र की तो हत्या हुई कि नहीं हुई परन्तु तंत्र की हत्या हुई और जन बच गया। और यह भी मैं कहना चाहता हूं कि अभी एक साथी ने कहा कि गृह मंत्री जी जल्लाद हैं जिन्होंने इस तरीके से हरयाणे के लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। मैं उन्हें जल्लाद के बदले में ब्राह्मण कहना पसंद करूंगा। जल्लाद तो वह होते हैं जिसके हाथ में तलवार हो जिन्दा व्यक्ति की गर्दन काटने के लिए। एक ब्राह्मण होते हैं जो मरे हुए मुर्दे को दाग लगाते हैं और वह जनेऊ पहने हुए होते हैं।...

(व्यवधान)

18 hrs.

एक माननीय सदस्य : ब्राह्मण नहीं महा-ब्राह्मण ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : तो मैं समझता हूं कि वह बड़ा ब्राह्मण है । इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि वहां पर जनतंत्र को तो रिश्वत-खोरों ने, भ्रष्टाचार ने और बेमानी ने पहले ही मार दिया था । उस मरे हुए जनतंत्र को हमारे गृहमंत्री ने दाग लगा दिया है ।

इस के साथ-साथ कहा जाता है कि आज काला दिन है । मैं मानता हूं कि काला दिन है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह काला दिन जनता के लिए नहीं है, राजनैतिक लोगों के लिए है क्योंकि उन को इस कूचे से काला मुंह कर के निकलना पड़ा । देखिए, हरयाना की जनता ने दो दृश्य देखे । एक दृश्य तो कांग्रेसी राज के श्री भगवतदयाल शर्मा का था । हरयाने की जनता ने सोचा कि भ्रष्टाचारी कांग्रेसी लीडरों का राज जो अन्धेरी रात है वह समाप्त हो और दूसरा राज बने । वह अन्धेरी रात खत्म होकर, भगवत दयाल शर्मा का राज खत्म हो कर दूसरा राज आया । लोगों ने समझा कि दिन निकल आया । लेकिन दिन तो निकला जरूर लेकिन जो लोग दिन में काम करते थे उन्होंने उसे दिन ही नहीं रखा, उस के साथ दहाड़ा और लगा दिया । दिन दहाड़े वह सब काम होने लगा । शायद संविधान की जो बारीकियां हैं उन में से क्या निकले यह सब मैं नहीं कह सकता लेकिन वह गरीब जनता, वह मासूम जनता जो संविधान को नहीं पढ़ सकती, वह तो यह देखेगी कि हमारे यहां कैसी हुकूमत चल रही है । जिस भ्रष्टाचारी हुकूमत के नीचे वह पिसी जा रही थी चाहे वह कांग्रेस की थी, चाहे गैर-कांग्रेसी की थी, आज हरयाने की जनता उससे छुटकारा पाना चाहती थी, और मैं यह कहना चहता हूं कि इन सारे मामलों में कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती । इन 20 वर्षों में कांग्रेस ने लोकतंत्र में जो गलत परंपराएं डालीं उस ने एक-एक व्यक्ति के हृदय में यह अविश्वास पैदा कर दिया है कि चाहे वह कोई काम किसी नीयत से करने चले हों, लेकिन उनकी नीयत को कोई ठीक नहीं मानता । और इसीलिए हमें शंका है । यह भी शंका होती है कि राव बीरेन्द्र सिंह को जो फांसी पर चढ़ाया गया वह कहीं चंडीगढ़ की वजह से तो नहीं चढ़ाया गया क्योंकि उसने चंडीगढ़ के मामले में आंखें दिखा दी थीं दिल्ली में तख्त पर बैठी हुई इस सरकार को कि मैं चंडीगढ़ नहीं दूंगा । कुछ लोगों को यह भी शंका होती है कि शायद सत्ता की पुन : प्राप्ति के लिए ऐसा किया गया । कुछ लोगों को और भी शंकाएं होती हैं । यह भी कहा जाता है कि असेम्बली को बुलाना चाहिए था । लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं कि असेम्बली बुलाना इस का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि शाम को असेम्बली खत्म होती और सुबह फिर वह इधर-उधर हो जाते तो किया क्या जाता ? तो आज न केवल कांग्रेस बल्कि सारे देश के जितने भी राजनैतिक दल हैं उन सब के लिए एक मौका है कि अपना आत्म-निरीक्षण करने का और पार्लियामेंट के सीनियर मेम्बरस की जिस में विरोधी दल के भी प्रतिष्ठित मेम्बर हों एक कमेटी बिठानी चाहिये । जिन लोगों ने चाहे वह कांग्रेस के रहे हों या गैर-कांग्रेसी रहे हों जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया हो उनकी जांच होनी चाहिए और अपने-अपने दल के लोगों को सजा देनी चाहिए ।

आज गवर्नर की रिपोर्ट पर तो यह हो गया । अब जनता के हाथों में मामला आया है । अगर कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेता ईमानदार हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी चुनाव करना चाहिए और यह मामला जनता के हाथों में जाना चाहिए । हमें गवर्नर की रिपोर्ट को एक तरफ रख कर जनता की रिपोर्ट लेनी चाहिए और राष्ट्रपति का शासन एक तरफ रख कर जनता का शासन लाना

चाहिए और मैं समझता हूं कि घबराने की बात नहीं है । विरोधी दलों के लिए । जो कुछ कांग्रेस ने किया है उस को देखते हुए जब चुनाव होगा तो जनता का जो फैसला होगा, वह सही फैसला होगा क्योंकि जनता ऊब चुकी है भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों से और उन भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों ने शायद फैसला लिया होगा या न लिया होगा लेकिन जनता जरूर फैसला लेगी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon'ble Home Minister.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : श्रीमन्, स्पीकर साहब अभी हम को वादा करके गए हैं । आप मुझे पांच मिनट भी नहीं दे सकते । भरे हाउस में स्पीकर साहब वादा करके गए हैं । आप लिस्ट देखिएगा । सब से ज्यादा चोट हमें लगी है और हमें ही मौका नहीं दिया जायेगा ?....

MR. DEPUTY-SPEAKER : He may please resume his seat.

श्री यशपाल सिंह : श्रीमान् **

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing will go on record.

श्री यशपाल सिंह : **

(Shri Sheo Narain stood up)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You will have to resume your seat.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सदन चाहे तो टाइम बढ़ा सकते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : **

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have never promised anything. Please resume your seat. This will not go on record.

(Some Hon'ble Member from Opposition stood up).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you going to encourage this type of behaviour. I am asking your leader.

SHRI YASHPAL SINGH : **

MR DEPUTY-SPEAKER : It will not be taken down. If he behaves like this, Mr. Joshi, I will have to take action. I appeal to you to restrain him. So many Members have given the adjournment motion and if everyone of them is to be given an opportunity, there will be no end to the debate.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : थोड़ा समय बढ़ा दिया जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already extended the time to accommodate some people.

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि स्पीकर साहब ने इन्हें मौका देने के लिए कहा था, अगर यह सही है तो इनको दो मिनट टाइम दे दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह सही नहीं है । लेकिन आप सब जब कह रहे हैं तो दो मिनट का टाइम मैं इनको दिए देता हूं ।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, न कभी मैं उसके लिए आग्रह करता हूं । लेकिन चूंकि इस के साथ मेरा अपना सम्बन्ध है, इस लिये मैं खड़ा हुआ हूं । हमारे भाई माननीय रणधीर सिंह ने दो बातें बिलकुल सच कहीं हैं—एक तो यह कि उन्होंने 40 साल तक भैंस का दूध पिया है, । हमारे स्वास्थ्य शास्त्र की, योग शास्त्र की, जिसको हैल्थ का शास्त्र कहते हैं, उसकी यह रिसर्च है कि भैंस का दूध अक्ल को सबसे ज्यादा मोटा करता है । उन्होंने ठीक कहा है ।

दूसरी बात, भाई रणधीर सिंह ने इस सरकार को होमेज पे किया है—यह बिलकुल

**Not recorded.

[श्री यशपाल सिंह]

सही किया है। अंग्रेजी दस्तूर के मुताबिक मरे हुए को होमेज पे किया जाता है। चूंकि इस सरकार की पोलिटिकल डेथ हुई है, इस लिये भाई रणधीर सिंह ने सच कहा है। अंग्रेजी दस्तूर के मुताबिक जिन्दे को तो ट्रिब्यूट पेश किया जाता है।

मेरी अर्ज श्रीमन्, यह है कि जनतन्त्र को हमने यहां लाकर इसलिये खड़ा नहीं किया था, गांधी जी के नेतृत्व में हम ने इस लिये लड़ाई नहीं लड़ी थी कि यहां पर वन-मैन शो होगा आप से मेरी अर्ज यह है कि "इट इज नेवर टू लेट टु मेन्ड।" मैं आपका हितैषी हूं, आप का खैरख्वाह हूं, मैं आपको गलत राय नहीं दे सकता। मेरे धर्म शास्त्रों की यह आज्ञा है—

> "सकि सखा साधु न शास्ति यो ऽधिपम्
> हिताश्न यः संश्रृणुते सकि प्रभुः"

मेरा फर्ज आपको राय देना है, आपने गलत कदम उठाया है। आपने अन्याय किया है, उस गवर्नमेन्ट के साथ अन्याय किया है, जिसके साथ दो की मैजोरिटी है। आप इसको वापस लीजिये, अगर वापस नहीं ले सकते तो 15 दिन के अन्दर इलैक्शन कराइये और तब पब्लिक यह फैसला करेगी कि वह इन्हें चाहती है या राव वीरेन्द्र सिंह को चाहती है।

श्री शिवनारायण (वस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है—सठे साठ्यम समाचरेत्। मैं आज इस हाउस में बठा-बैठा श्री अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा रीड कर रहा था, उस पर उदासी छाई हुई थी, क्योंकि जन-संघ के प्रेजीडेन्ट श्री मधोक जी और प्रो० सोंधी—दो योग्य व्यक्तियों ने स्टेटमेन्ट दिये थे कि वहां पर प्रेजीडेन्ट रूल होना चाहिये।

वाजपेयी जी, सुनिये अब मेरी बारी है। अब उन को यह घबराहट है कि कल उत्तर प्रदेश की भी यही गति होने वाली है, यही परेशानी बेनर्जी साहब को भी है क्योंकि अब यह तलवार उन पर बजेगी।

यहां पर मध्य प्रदेश के झगड़े का जिक्र किया गया कि चीफ मिनिस्टर को राइट था विधान सभा बुलाने का, इसलिये राव वीरेन्द्र सिंह को भी राइट था, हम इससे कब इन्कार करते हैं, लेकिन वहां तो परिस्थिति ही दूसरी थी। 39 आदमी इस तरफ थे और 39 दूसरी तरफ थे। ऐसी हालत में "आइ एम वरिड एबाउट दिस गैमबलिग पौकेट।" मुझे तरस आता है बख्शी साहब पर, काश्मीर के बारे में भी आपको इसी तरह फैसला करना चाहिये। चूंकि दोनों तरफ 39-39 थे, इसी वजह से यह प्रोक्लेमेशन ईशू करना पड़ा। गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेजने के लिये मजबूर हो जाना पड़ा, हालांकि उस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज की जो रिपोर्ट है, परिस्थिति है, 39-39 की इसी वजह से प्रोक्लेमेशन ईशू हो गया।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की मैजोरिटी थी, लेकिन हमारे लोगों को इन लोगों ने करप्ट किया और राव वीरेन्द्र सिंह को इधर-उधर करके 6 महीने में करप्ट कर दिया और वहां पर इस तरह से गैम्बलिग होने लगी—यह बड़ी हैरानी की बात है।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के बहादुर आदमी हमारे देश के रक्षक हैं, एक-एक जवान सीमा पर डटा हुआ है। इसलिये बहुत खुशी हुई कि इस गवर्नमेंट ने बहुत जल्द स्टेप लिया। लेकिन इसी तरह से अब आप काश्मीर को ठीक करें, बंगाल को ठीक करें, बिहार को ठीक करें और उत्तर प्रदेश, को भी ठीक करें।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I have heard for the last four hours with interest the

debate on this double motion, if I may call it, because the first motion is by Shri Vajpayee, and the other is a statutory motion that I have moved for the approval of the Proclamation.

The main argument that was made against this Proclamation was a political argument, which is rather a biased argument. The main line is that this is a political action taken in the interests of the Congress Party, that there was some sort of conspiracy between the Central Government and the Governor. This is the usual type of argument which I must at the outset repudiate as a biased argument, untrue argument.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : A real type of repudiation.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Facts are not denied. Facts are facts.

SHRI Y. B. CHAVAN : The essence of the whole position is this: whether the assessment of the political situation that the Governor has made in his report is a valid assessment, a correct assessment, and whether the action that we have taken on the basis of that assessment is right or wrong. All other issues are irrelevant issues here.

No member has said with any conviction that that assessment was wrong. Even hon. Shri Ranga, when he spoke, said that he does not regret this legislature has gone, he does not regret that this Government has gone. I think Shri Vajpayee has moved this motion as a formality perhaps, I do not know whether in his heart of hearts he really wants to oppose this, because I can understand that as a leader of the opposition they have to say that they are opposed to this.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो आप तरक्की कर रहे हैं ।

श्री राम सेवक यादव : आप नजूमी कब से बन गये कि आप यह सब जान गये ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप के साथ बैठ कर जान गया हूं । As I said, for the first time, while moving a motion on behalf of the Government I am unhappy because this is not something that one can be proud of. I am really sad, really speaking.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Ashamed.

SHRI Y. B. CHAVAN : Not ashamed, but I am certainly sad, not only because a Government's power has to be taken over, but, as I said, because the situation has degenerated to such an extent that one has to take such an action. I am really sad about it.

This Governor's report is a sad commentary on the democratic way of life itself. That really speaking hurts me, and should hurt everybody.

Some member said that what has happened in Haryana is a mockery of democracy, that what is happening here is a mockery of the Constitution. Not at all. Ultimately, our whole Constitution is based on the fundamental principles of democracy. If there is a mockery of democracy in Haryana, and in order to remove that mockery if we have to take action under the Constitution, it cannot be a mockery of the Constitution. It is with a view to support the Constitution that we are taking this action.

श्री पीलू मोदी : सुना, कुछ समझे, ये यों ही ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. member who interrupts many times does not himself understand anything. He just makes fun of others, that is the difficulty about him.

What is the position there ? I am reading a report of the Chief Minister's speech from the *Patriot* of 11th November, in which the Chief Minister says :

> "The epidemic of defection among legislators has assumed a menacing and disturbing form in the

[Shri Y. B. Chawan]

State. The disease has spread so much that none could be relied upon. The Chief Minister alleged that some legislators defected from their parties because of money."

This is what the Chief Minister says.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : You are quoting his speech or a report ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I am reading a press report of his speech.

I am only talking of the feeling of the Chief Minister himself, that he thinks that this is a diseased condition. Every Member has been saying that what is happening in Haryana is bad. Each and every Member said that we cannot defend what was happening there. Nobody has any sympathy for that sort of thing. There are those who can say this and just get away with it. But the man who is legally responsible and has a duty to see and act in the State was the Governor. He just cannot say, "I see a diseased condition here and still I sit quietly about it." He is the person who has to take note of these things and act.

SHRI S. M. BANERJEE : Waiting up to the 3rd. (*Interruption*)

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. Member has not read the report carefully. The Governor has acted upon it, and he has said that suppose he had waited, he might have had a government with a majority of three or four, but how long would the Government last ? Because of defection, in the morning, "we have voted for you", it would be said, and in the evening something else would happen.

There is a popular saying in Haryana about the defections. The people of Haryana are wise, but unfortunately they are unlucky in having a representation like this. There is a popular saying in Haryana; I do not know whether it is true; but I have heard it. They have given very peculiar names to the defectors : *Aya Ram* and *Gaya Ram*.

Aya Ram's value is Rs. 20,000 and Gaya Ram's value is Rs. 40,000. This is the political situation in Haryana. The Haryana situation is a class by itself. It required a special action by itself. It is an unfortunate thing. (*Interruption*). I am not having any brief for any political party. I entirely agree with the sentiments expressed by Acharya Kripalani: all political parties have failed in Haryana's democratic life. We are all sad over it. Nobody can be proud of it. The Congress party has failed; the Jan Sangh has failed; every political party has failed. (*Interruption*). The hon. Member there has said that the Jan Sangh has not failed. I have a point about it. It is true that the Jan Sangh has not participated in that government. But, I should say, that does not absolve them from the responsibility for what has happened. Some of their members have also defected once or twice. But how can they say that "we have not participated in the government," when, with all their strength and moral support they were allowing this sort of thing to happen ? (*Interruption*). This is the moral position ! They did not want to participate, but they would take the position of a saint, stand aside, allow the situation to grow, and then take the position of a saint and say, "Oh, all others are not good." (*Interruption*). This is the position.

SHRI S. M. BANERJEE : Immorality in your party.

SHRI Y. B. CHAVAN : If there is immorality in my party, I have the guts to admit it, but you do not admit it. That is the difficulty. What I am saying is this : all the political parties have failed. What is the solution for that ? The ultimate solution that I offer is, take the whole think back to the hands of the people. This proclamation is not meant to continue this power in the hands of the President a day longer. It is just for a few months, and then we want to go back to the people and tell them, "Choose your representatives right again."

The Constitution itself has provided a mechanism. The Constitution-framers were very wise people; they knew that such difficulties would arise and they anticipat-

ed these difficulties. (*Interruption*). When the whole thing has resulted in such a bad condition, what is the Governor to do ? Is the Governor supposed, expected, merely to wait and whoever defects, he is brought to him and he is allowed to become a Minister and sworn in ? (*Interruption*)

AN HON. MEMBER : Even the Chief Minister.

SHRI Y. B. CHAVAN : That is true. Even the Chief Minister. The hon. Member seems to agree with me. I am very glad. The point that we are ultimately discussing is the assessment as expressed in the report of the Governor. The Government has done only one thing. When they saw that there was irrefutable logic in the report, when there was objectivity in the report and there was wisdom in the assessment of the situation in the report, in that situation, it was the duty of the Government of India to accept it. We would have failed in our duty had we not accepted the report. If it were a question of party interests, I would have recommended something else. We are not taking any action in the interest of any political party. I can say with my hand on my conscience that we have come with this recommendation of acceptance of this proclamation with a national sense of responsibility. I have no doubt in my mind about it. It is a rather hard and unhappy decision to take over the administration of a State under President's rule. It is not something very happy. But one has to do sad duties sometimes.

SHRI NATH PAI : I am a little intrigued, Sir. This is a new thing. I know a man can put his hand on his heart. But he said, he can put his hand on his conscience. Where exactly is his conscience located ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I can say, my conscience is in my heart.

SHRI S. M. BANERJEE : Why don't you lay it on the Table ?

SHRI Y. B. CHAVAN : This is an absolutely essential step that had to be taken and therefore, I have no hesitation in my mind in recommending the acceptance of this Proclamation by this House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद से एक बात साफ हो गई है कि हरियाणें में राष्ट्रपति राज लागू करने के लिए कोई संवैधानिक औचित्य सरकार के पास नहीं है । जितने तर्क दिये गये हैं राज्यपाल की रिपोर्ट स्वीकार करने के पक्ष में या उस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणे की विधान सभा को भंग करने के पक्ष में वे सारे तर्क ऐसे हैं जो संविधान में से नहीं निकले और जिनका कि इलाज संविधान की धारा का इस प्रकार दुरुपयोग करके नहीं किया जा सकता । किसी कांग्रेस के मैम्बर ने या चह्वाण साहब ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है कि जो पश्चिम बंगाल में मानदंड लगाया जा रहा है वह हरियाणे में क्यो नहीं लगाया गया ? राज्यपाल ने विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए जोर क्यों नहीं दिया ? क्योंकि कंडीशंस डिफैंट हैं, हालात अलग हैं । अलग गज से इसलिए नापा जा रहा है कि हरियाणे की गैर-कांग्रेसी सरकार को तोड़ना उद्देश्य है और पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का उद्देश्य है ।

मैं ने पहले भी कहा था और इस बात का भी समाधानकारक उत्तर नहीं दिया गया । एक ही तर्क दिया गया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के समर्थन में दल बदले जा रहे थे तो क्या दलबदल का इलाज राष्ट्रपति का शासन है ? कांग्रेस का सत्ता पर से एकाधिकार समाप्त हो गया । अन्य दल अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते तो देश में मिली जुली सरकारें चलने वाला जब तक संक्रमणकाल है मिल जुले मंत्रिमंडल बनेंगे । उनमें इस प्रकार के अप्रिय दृश्य भी दिखाई देंगे । अगर इन दृश्यों को टालना है तो राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई हल निकालना होगा । राज्यपाल के हाथों में केन्द्रीय सरकार खेले तो न लोकतंत्र मजबूत होने वाला है न संविधान की गरिमा की रक्षा होने वाली है ।

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

गृह मंत्री हरियाणे के कांग्रेसी नेताओं की निन्दा करने में शामिल हैं और उनकी निन्दा करके वह दिखाना चाहते हैं कि वह बड़े निष्पक्ष हैं । मैं पूछता हूं कि एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता की हैसियत से हरियाणे में जो कुछ हो रहा था, कांग्रेस पार्टी जो कुछ कर रही थी, उसे रोकने के लिए उन्होंने क्या किया ? और बात केवल हरियाणे की नहीं है जनता ने स्वतन्त्र पार्टी के एक सदस्य को लोकसभा में चुन कर भेजा, श्री जमना लाल, वह सदस्य स्वतन्त्र पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में चले गये ।

प्रधान-मंत्री ने, उप-प्रधान मंत्री ने, गृह मंत्री ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस में कोई सदस्य नहीं लिया जायेगा, पहले त्यागपत्र दे कर जनता से दोबारा विश्वास सम्पादन कर के दिखाओ । हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं पर जिम्मेदारी डालने से नहीं चलेगा । केन्द्र में बैठे हुए कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं ? दल-बदल की समस्या को अगर हल करना है, तो वह हल राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए । मैं जानता हूं कि सैद्धान्तिक मतभेद के आधार पर दल बदले जा सकते हैं । मैं अपने उन मित्रों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने श्री अशोक मेहता पर कुछ आक्षेप किया है । मुझे उन आक्षेपों से चोट लगी है । श्री अशोक मेहता का कांग्रेस में जाना हम पसन्द नहीं करते हैं, लेकिन मैं एक क्षण के लिए भी यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि श्री अशोक मेहता मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में गए ।

एक माननीय सदस्य : प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बनने के लिए ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : लेकिन अवसरवादिता के आधार पर दल बदले जा सकते हैं और उसका इलाज राजनीतिक दलों को ढूंढना होगा । क्या कांग्रेस इस के लिए तैयार है ? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है । हम इसके लिए तैयार हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सब को पूछिए ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : सब को पूछने की बात न कीजिए । अगर कांग्रेस तैयार है, तो हम उसका समर्थन करने के लिये तैयार हैं ।

लेकिन इस का इलाज यह नहीं है कि सरकार दल बदलने की समस्या को रोकने के लिए राष्ट्रपति-शासन लागू करे । मान लीजिये, अगर हरियाणा में चुनाव हुए और चुनाव के बाद भी कोई दल स्पष्ट बहुमत में नहीं आया या कांग्रेस की तरह से आया और कुछ कांग्रेसी टूट कर विपक्ष में चले गए, तो फिर क्या स्थिति होगी ? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन फिर लागू कर दिया जायगा ? हरियाणा में जो कांग्रेसी टूट कर आए, उन को किसी और दल ने नहीं लिया; भारतीय जनसंघ ने किसी भी टूटने वाले सदस्य को नहीं लिया । मगर जो चौधरी देवीलाल कांग्रेस को लात मार कर निकल आए थे, जब वह फिर कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस ने उनको स्वीकार कर लिया । हरियाणा में जब श्री हरिद्वारीलाल कांग्रेस छोड़ कर गए और दूसरी सरकार में भाग लिया, तो उन्होंने विधान सभा की सीट छोड़ दी, फिर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस को पराजित कर के फिर से चुन कर आए । अभी किसी कांग्रेस के नेता को ऐसा उदाहरण रखना बाकी है ।

केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जो कुछ हुआ है उससे हमें बड़ा दुख है और हम बड़े दुखी होकर राष्ट्रपति-शासन लागू कर रहे हैं । गृह मंत्री कहते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है; अगर राजनीतिक उद्देश्य होता तो हम कांग्रेस को फिर ले आते । कांग्रेस को कैसे ले आते ? कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है । जहां वह कांग्रेस को अनैतिक ढंग से ला सकते हैं वहां वह चूके नहीं ।

लेकिन हरियाणा में जब दूसरे पक्ष का बहुमत था तो वह कांग्रेस को कैसे ले आते ? लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लागू करके वह चोर दरवाजे से कांग्रेस को नहीं ले आए ?क्या राष्ट्रपति शासन अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का शासन नहीं है ? अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का शासन लाकर भी मंत्री महोदय यह दावा करते हैं कि हम ने पार्टी के स्वार्थों की चिंता नहीं की !

अगर यह आवश्यक हो गया था कि हरियाणा में आम चुनाव होने चाहिए तो राव बीरेंद्र सिंह के मंत्री-मंडल को बनाए रख कर भी आम चुनाव हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे ? हर पांच वर्ष बाद जब देश में आम चुनाव होते हैं तो कांग्रेस सरकारें भंग नहीं की जाती हैं; वे चलती रहती हैं और चुनाव के आदेश दिये जाते हैं।

श्री रणधीर सिंह : गन्द कैसे साफ होता ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहा जा रहा है कि गन्द कैसे साफ होता। श्री बरुआ ने कहा कि हरियाणा से बू आ रही है। अगर हरियाणा से बू आ रही है तो केन्द्रीय सरकार के निर्णय से उससे भी ज्यादा बू आ रही है।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि राज्यपालों को छोटा डिक्टेटर बनाने की भूल न की जाये। राजनीतिक रोग का इलाज राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। अगर सरकार और कांग्रेस दल राज्यपालों को संविधान के साथ खिलवाड़ करने का मौका देंगे, अगर चुने हुए मुख्य मंत्री की तुलना में राज्यपाल की बात अन्तिम समझी जायेगी तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जायेगा और किनारे पर बैठे हुए तानाशाही लाने वाले उन्हीं के बनाए हुए राजमार्ग पर चल कर दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सत्ता को भी नहीं रहने देंगे।

इस लिए यह आवश्यक है कि यह सरकार वक्त की आवाज को सुने और लोकतंत्र की रक्षा करे। हरियाणा में उसने जो कुछ किया है उस से न तो उस की प्रतिष्ठा बढ़ी है और न लोकतंत्र की।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now put the motion of Shri Vajpayee to the vote of the House. The question is :

> "That this House regrets that the Government of India did not reject the report dated the 17th November, 1967 of the Governor of Haryana to the President recommending the issue of proclamation, laid on the Table of the House on the 21st November, 1967, inasmuch as the Government of Haryana enjoyed majority in the Legislature and functioned in accordance with the provisions of the Constitution."

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, before you take votes may I request that at least the defectors should not vote ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : That includes Shri Banerjee also.

The Lok Sabha divided.

[Division No. 4] **18.42 hrs.**

AYES

Adichan, Shri P. C.
Amin, Shri R. K.
Anbazhagan, Shri
Anirudhan, Shri K.

Banerjee, Shri S. M.
Bharat Singh, Shri
Brij Bhushan Lal, Shri
Deo, Shri K. P. Singh
Deo, Shri P. K.
Desai, Shri C. C.
Devgun, Shri Hardayal
Dwivedy, Shri Surendranath
Ghosh, Shri Ganesh
Goel, Shri Shri Chand
Gowd, Shri Gadilingana
Gowder, Shri Nanja
Gupta Shri Kanwar Lal
Joshi, Shri Jagannath Rao
Joshi, Shri S. M.
Kameshwar Singh, Shri
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Karni Singh, Dr.
Kothari, Shri S. S.
Koushik, Shri K. M.
Krishnamoorthi, Shri V.
Kundu, Shri S.
Limaye, Shri Madhu
Meena, Shri Meetha Lal
Menon, Shri Vishwanatha
Misra, Shri Srinibas
Modak, Shri B. K.
Mody, Shri Piloo
Molahu Prasad, Shri
Naik, Shri R. V.
Nambiar, Shri
Narayanan, Shri
Nath Pai, Shri
Nayar, Shrimati Shakuntala
Nihal Singh, Shri
Rajaram Shri
Ramamurti, Shri P.
Ranga, Shri
Rao, Shri V. Narasimha
Ray, Shri Rabi
Reddy, Shri Eswara
Samanta, Shri S. C.
Saminathan, Shri
Santosham, Dr. M.
Sen, Shri Deven
Sezhiyan, Shri
Sharda Nand, Shri
Sharma, Shri Beni Shanker
Sharma, Shri N. S.
Sharma, Shri Yajna Datt
Somani, Shri N. K.
Sondhi, Shri M. L.
Sreedharan, Shri A.
Suraj Bhan, Shri
Tyagi, Shri O. P.
Umanath, Shri
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Viswambharan, Shri P.
Viswanatham, Shri Tennei
Viswanathan, Shri G.
Yadav, Shri Ram Sewak
Yashpal Singh, Shri

NOES

Ahmad, Dr. I.
Ahmed, Shri F. A.
Awadesh Chandra Singh, Shri
Bajpai, Shri Shashibhushan
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Basu, Dr. Maitreyee
Baswant, Shri
Bhagat, Shri B. R.
Bhakt Darshan, Shri
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhola Nath, Shri
Bohra, Shri Onkarlal
Brahma, Shri Rupnath
Buta Singh, Shri
Chanda, Shri Anil K.
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrika Prasad, Shri
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri Y. B.
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhury, Shri J. K.
Dalbir Singh, Shri
Damani, Shri S. R.
Desai, Shri Morarji
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ering, Shri D.
Gajraj Singh Rao, Shri
Gandhi, Shrimati Indira

Ganga Devi, Shrimati
Gautam, Shri C. D.
Gavit, Shri Tukaram
Ghosh, Shri Parimal
Govind Das, Dr.
Hazarika, Shri J. N.
Heerji Bhai, Shri
Hem Raj, Shri
Himatsingka, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jagjiwan Ram, Shri
Karan Singh, Dr.
Kasture, Shri A. S.
Kavade, Shri B. R.
Khan, Shri M. A.
Khanna, Shri P. K.
Kinder Lal, Shri
Kripalani, Shrimati Sucheta
Krishnan, Shri G. Y.
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Maharaj Singh, Shri
Mahida, Shri Narendra Singh
Malimariyappa, Shri
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Mane, Shri Shankarrao
Masuriya Din, Shri
Mehta, Shri Ashoka
Mehta, Shri P. M.
Menon, Shri Govinda
Mishra, Shri Bibhuti
Mishra, Shri G. S.
Mohammad Yusuf, Shri
Mohinder Kaur, Shrimati
Mukerjee, Shrimati Sharda
Murti, Shri M. S.
Padmavati Devi, Shrimati
Pahadia, Shri Jagannath
Pant, Shri K. C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manibhai J.
Patil, Shri Deorao
Poonacha, Shri C. M.
Pramanik, Shri J. N.
Qureshi, Shri Mohd. Shaffi
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Rajani Gandha Kumari
Rajasekharan, Shri
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Kishan, Shri
Ram Sewak, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Dr. K. L.
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri J. Ramapathi
Rao, Shri Thirumala
Rao, Dr. V. K. R. V.
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri P. Antony
Reddy, Shri R. D.
Reddy, Shri Surendar
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Sankata Prasad, Dr.
Sapre, Shrimati Tara
Sarma, Shri A. T.
Savitri Shyam, Shrimati
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Sethuramae, Shri N.
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri M. R.
Shastri, Shri B. N.
Shastri, Shri Sheopujan
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shinkre, Shri
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri Vidya Charan
Sidheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri D. V.
Sinha, Shri Mudrika
Sinha, Shri Satya Narayan
Snatak, Shri Nar Deo
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Sudarsanam, Shri M.
Supakar, Shri Sradhakar
Surendra Pal Singh, Shri
Swaran Singh, Shri
Venkatasubbaiah, Shri P.
Vyas, Shri Ramesh Chandra

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result of the division is :

Ayes—66

Noes—143

The 'Noes' have it; the 'Noes' have it.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I shall put to the vote of the House the motion moved by the Home Minister.

The question is :

"That this House approves the Proclamation issued by the President of India on the 21st November, 1967, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Haryana."

The motion was adopted.

18·45 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 22, 1967/Agrahayana 1, 1889 (Saka).

M81LSS/67—1010—13-2-68—GIPF.